



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]
No. 201]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 1991/ज्येष्ठ 9, 1913
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 1991/JYAISTHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक

प्रध्याय-1

व्यवहार आयोग

माधाराण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1991

सा.का.नि. 283(अ) —एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्या 54) की धारा 18 और 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियमन, 1974 का अधिक्रमण, उसके अधिक्रमण किए जाने से पूर्व किए गए कार्यों अथवा करने में छोड़े गए कार्यों के सिवाय, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन विनियमों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विनियम, 1991 कहा जा सकता है। ये विनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा प्रतीत न हो, इन विनियमों में —

(क) "अधिनियम" से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम सं. 54) अभिप्रेत है,

(ख) अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट "कोई अन्य हितवद्ध व्यक्ति" में विनिर्माता, प्रदायकर्ता, थोक-विक्रेता, फुटकर विक्रेता और व्यापारियों और

उपभोक्ताओं के संगम, विनिर्माताओं के कर्मचारी और वितरण-व्यापार में लगे हुए व्यक्ति हैं;

(ग) "न्यायपीठ" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन विरचित न्यायपीठ है,

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त किया गया आयोग का अध्यक्ष है,

(ङ) "पक्षकार" में शिकायतकर्ता (चाहे वह व्यक्ति उपभोक्ता हो अथवा उपभोक्ताओं का या व्यापारिक रजिस्ट्रीकृत संगम हो, चाहे वे यथा स्थिति केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के महानिदेशक हों) और वे प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थीगण सम्मिलित होंगे जिनके विरुद्ध कोई जांच अथवा कार्यवाही संस्थित की गई है अथवा राहत चाही गई है किन्तु धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (4) अथवा धारा 36ख के खंड (घ) के अधीन सूचना देने वाला इसमें सम्मिलित नहीं होगा :

परन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए अपने ज्ञान या जानकारी के आधार पर आयोग द्वारा स्वयं संस्थित की गई कार्यवाही अथवा आदेशित जांच में किसी प्रत्यर्थी के विरुद्ध की गई ऐसी जांच या कार्यवाही करने के लिए केवल महानिदेशक को ही एक मात्र पक्षकार माना जाएगा,

परन्तु यह और कि जब शिकायतकर्ता शिकायत को भ्रांति नहीं बढ़ाता या उस शिकायत में कोई रचि नहीं दिखाता तो आयोग की अनुशा से महानिदेशक उन कार्यवाहियों को पूर्ण रूप से स्वयं चलाने का हकदार होगा,

(च) "करार का पक्षकार" में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए माना जाने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है,

(छ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों को लागू करते हुए "न्यायालय" के प्रति निर्देश से यह समझा जाएगा कि आयोग के प्रति निर्देश किया गया है और इसी प्रकार "वादी" या "प्रतिवादी" के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि आयोग के समक्ष समुचित पक्षकारों के प्रति निर्देश किया गया है।

(ज) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों को लागू करते समय "वाद" या याचिकाओं के प्रति निर्देश को अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियों के प्रति निर्देश समझा जाएगा,

(झ) "सचिव" का तात्पर्य आयोग का सचिव है और इसमें आयोग का उप-सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त-निदेशक (विधि) और उप-निदेशक (विधि) भी सम्मिलित हैं,

(ञ) धारा का तात्पर्य अधिनियम की धारा है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु

जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, क्रमशः वही अर्थ दिया जाएगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. आयोग की भाषा, आयोग की कार्यवाहियां अंग्रेजी अथवा हिन्दी में होंगी।

4. आवेदनों और निवेदनों आदि की भाषा-अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में आवेदन, निवेदन, दस्तावेज अथवा कागजात आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनके साथ उनका अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. दस्तावेजों का अनुवाद—विनियम 4 के अधीन जिन दस्तावेजों का अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद किया जाना अपेक्षित है, उनका अनुवाद आयोग द्वारा निदुक्त अथवा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा :

परन्तु किन्हीं समुचित कार्यवाहियों में कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा स्वीकार अनुवाद को आयोग सही अनुवाद के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

6. आयोग का कार्यालय—आयोग का केन्द्रीय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देशित समय पर खुलेगा।

7. कार्यवाहियों का स्थगन—अगर कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आयोग को पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो वह पक्षकारों को अथवा उनमें से किसी को समय प्रवृत्त कर सकता है और समय-समय पर कार्यवाहियों की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

8. एक-पक्षीय सुनवाई—जहां पर सुनवाई के निश्चित दिन को अथवा किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, यदि कार्यवाही के पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं वहां पर जब तक कि आयोग द्वारा कार्यवाहियां स्थगित नहीं की जाती हैं, इस प्रकार उपस्थित न होने वाले पक्षकारों की अनुपस्थिति में जारी रहेंगी।

9. आयोग के समक्ष अभिवचन—आयोग के समक्ष फाइल किए जाने वाले अपेक्षित सभी आवेदन, उत्तर, प्रत्युत्तर, पूरक-अभिवचन अथवा अन्य दस्तावेज पूरे आकार के कागज पर उबल स्पेस में एक ही तरफ टंकित किए जाएंगे।

10. दस्तावेजों, कागजों की सत्य प्रतिलिपियों और निरीक्षण:—

(1) आयोग के समक्ष की कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार धारा 17, 18 और 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सचिव को सम्बोधित करते हुए इस सम्बन्ध में आवेदन करता है तो उसे विनिश्चित फीस और प्रभार का संवाय करने पर अभिवचनों की प्रतियों और अन्य दस्तावेजों अथवा

कार्यवाहियों के अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए अथवा उनका निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।

(2) धारा 17, 18 और 60 के उपबंधों को अधीन रहते हुए उप-विनियम (1) में यथा उल्लिखित फीस का संदाय करने पर ऐसी प्रतियों को प्राप्त करने के लिए अथवा उनका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने पर किसी आवेदन करने पर ऐसे व्यक्ति को भी आयोग अनुज्ञात कर सकता है जोकि कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं है।

(3) आयोग के किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ही निरीक्षण अनुज्ञात किया जाएगा और कार्यवाहियों के दस्तावेजों की प्रतियां फाइल से निकालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। न निरीक्षण के केवल टिप्पण ही लिए जा सकते हैं।

(4) यथा विहित फीस का संदाय करने पर ही उप-विनियम (1) अथवा (2) के अधीन अपेक्षित कार्यवाहियों की प्रतियों को आयोग के सचिव अथवा इस संबंध में आयोग द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में सत्यापित किया जा सकता है।

(5) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रत्येक वह अधिकारी जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो अथवा अन्वेषण और रजिस्ट्रेशन के महानिदेशक को सभी युक्तियुक्त समयों पर बिना कोई प्रभार दिए आयोग की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने उनकी प्रतियां प्राप्त करने अथवा उनमें से किसी दस्तावेज के उद्धरण प्राप्त करने का हक होगा। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में मांगी गई ऐसी प्रतियों और उद्धरणों को आयोग उन्हें देगा।

11. आयोग की रिपोर्ट, आदेश अथवा निर्णय—

(1) अध्यक्ष और सदस्य तारीख सहित आयोग की प्रत्येक रिपोर्ट, आदेश अथवा निर्णय पर हस्ताक्षर करेंगे। परन्तु अध्यक्ष अथवा वह सदस्य जो अंतिम निष्कर्ष से विसम्मति रखता है अपने कारणों को अलग से अभिलिखित करते हुए तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।

(2) अगर किसी न्यायपीठ के सदस्य समान संख्या में राय में विभिन्नता रखते हैं तो वे अलग से तारीख सहित हस्ताक्षर करते हुए अपने विचारों को अभिलिखित करेंगे। तब अगर अध्यक्ष उस न्यायपीठ का सदस्य नहीं है तो वह अपनी राय दे सकेगा अथवा अगर वह उस न्यायपीठ का सदस्य है या अन्यथा वह अपनी राय नहीं देना चाहता है तो पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अगर वह आवश्यक समझे तो किसी अन्य सदस्य को अपनी राय देने के लिए निर्देश दे सकता है। इसके

पश्चात् बहुमत के आधार पर मामले को विनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वह रिपोर्ट, जो अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित है, उस सरकार को सचिव के हस्ताक्षर से भेजी जाएगी।

12. विहित समय का बढ़ाया जाना—इन विनियमों द्वारा नियत अथवा आयोग के आदेश द्वारा किसी कार्य को करने के लिए आदेशित कोई समय सीमा आयोग के आदेश द्वारा बढ़ायी जा सकेगी (चाहे उसका पहले से अवसान हो चुका है अथवा नहीं) अथवा उसको न्यून किया जा सकेगा।

13. सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुपालन और मामले में उसके लागू न किए जाने का प्रभाव—

(1) इन विनियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहने से कोई भी कार्यवाही ऐसी असफलता के कारण केवल तब तक असफल नहीं हो जाएगी जब तक कि आयोग की यह राय न हो कि ऐसी असफलता के परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हुई है।

(2) जहां पर इन विनियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है वहां पर धारा 12 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जैसे कि आयोग द्वारा समीचीन समझा जाए उस सीमा तक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) उसकी कार्यवाहियों को लागू होगा।

14. नोटिस अथवा अन्य दस्तावेजों का दिया जाना—

(1) प्रत्येक नोटिस अथवा दस्तावेज, जिसको—

(क) किसी व्यक्ति को तामील किया जाना है अथवा दिया जाना है उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा कूरियर सेवा द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा उस व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति द्वारा ऐसी तामील को स्वीकार करने के लिए अधिकार प्राप्त व्यक्ति को संबोधित करते हुए उस पते पर, जिस पर उसने ऐसी तामील के लिए कहा है, अथवा उस स्थान को, जहां पर वह व्यक्ति अथवा उसका अभिकर्ता साधारणतया रहता है अथवा कारबार करता है अथवा स्वयं लाभ के लिए कार्य करता है, भेजा जा सकेगा।

(ख) सचिव को दिया जाना है अथवा उसके समक्ष फाइल किया जाना है, उसे सचिव को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

(2) प्रेषिती अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पावती अथवा डाक कर्मचारी द्वारा किए गए इस पृष्ठांकन से कि प्रेषिती अथवा उसके अभिकर्ता से उसे प्राप्त करने से इंकार कर दिया है

अथवा कूरियर का या स्पीड पोस्ट के कर्मचारी द्वारा दिए गए इस प्रमाण पत्र से कि तामील कर दी गई है, इसके बारे में प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि यह तामील किए जाने का सबूत है।

(3) किसी व्यावसायिक संगम को तामील अथवा दिए जाने के लिए अपेक्षित नोटिस अथवा दस्तावेज उस संगम के सचिव, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारियों को ऐसे भेजे जा सकते हैं अगर वह संगम कोई निगमित निकाय नहीं है।

(4) यथा स्थिति केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार को तामील करने अथवा दिए जाने के लिए अपेक्षित नोटिस अथवा दस्तावेज के समुचित मंत्रालय अथवा विभाग के सचिव को संबोधित होगा और उन्हें ही भेजा जाएगा और उसे उप विनियम (1) के खंड (ख) के विनिर्दिष्ट तरीके से तामील किया जाएगा।

(5) जांच से संबंधित किसी नोटिस अथवा दस्तावेज की तामील—

(क) जहां पर जांच किसी कंपनी या निगम के विरुद्ध की जा रही है तो कंपनी या निगम के सचिव अथवा किसी भी निदेशक अथवा उस कंपनी अथवा निगम के मुख्य अधिकारी को अथवा उसे डाक द्वारा उस कंपनी या निगम के उस रजिस्टर्ड कार्यालय को अथवा उस कंपनी निगम के उस स्थान को भेजे जा सकते हैं जहां पर वह साधारणतया अपना कारबार करता है।

(ख) जहां पर जांच किसी फर्म के विरुद्ध है वहां पर जांच संबंधी नोटिस की तामील भागीदारी कारबार के मुख्य स्थान पर नोटिस की तामील किए जाने के समय भागीदारी कारबार को नियंत्रित कर रहे अथवा उसका प्रबंध कर रहे किसी एक भागीदार पर अथवा अधिक भागीदारों पर की जा सकती है।

(ग) एकमात्र व्यापारिक फर्म के मामले में उसके स्वत्वधारी को की जा सकती है।

15. खर्च—(1) आयोग उसके द्वारा दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन रहते हुए अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों के खर्चों का अवधारण कर सकता है।

(2) इन खर्चों का संदाय आदेश के दिन से तीस दिनों के भीतर अथवा उस समय के भीतर किया जा सकेगा जिसके प्रति आयोग अपने आदेश में निर्देश दे।

(3) आयोग के आदेश और खर्चों से संबंधित अधि-निर्णय का निष्पादन उसी रीति में किया जाएगा जिस प्रकार कि सिविल न्यायालयों के आदेश का किया जाता है और ऐसे आदेश को निष्पादन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश के उपबंध लागू होंगे।

16. आयोग द्वारा पारित किए गए आदेशों का प्रवर्तन :

(1) सचिव आयोग द्वारा पारित आदेशों का संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रवर्तन और अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और अगर आवश्यक हुआ तो अपेक्षित जांच करने के लिए, जो आयोग के महानिदेशक द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो सहायक-निवेशक की पक्ति से नीचे का न हो, आदेश प्राप्त करेगा।

(2) आयोग के आदेशों के अनुपालन संबंधी समुचित मामलों के संबंध में महानिदेशक आयोग को जानकारी देगा और ऐसे अनुपालन के संबंध में अन्वेषण करने के लिए निर्देश प्राप्त कर सकता है।

अध्याय 2

प्रारम्भिक अन्वेषण

17. अन्वेषण के लिए आदेश और इसका प्रभाव—

(1) आयोग अवरोधक अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार के मामले में अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) अथवा धारा 36ख के अधीन यथास्थिति परिवाद निर्देश आवेदन अथवा सूचना प्राप्त होने पर अथवा अपने स्वयं के ज्ञान के अनुसार महानिदेशक अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा जो सहायक निदेशक की पक्ति से नीचे का जोन हो प्रारम्भिक जांच किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण—जब आयोग धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (1) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर प्रारम्भिक अन्वेषण के लिए आदेश देता है अथवा किसी संगम द्वारा किए गए परिवाद की दशा में धारा 36ग के अधीन अनिवार्यतः प्रारम्भिक अन्वेषण अपेक्षित है वहां पर ऐसा अन्वेषण महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

(2) विनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा अन्वेषण के लिए किए गए आदेश से यह माना जाएगा कि यह अधिनियम के अधीन जांच का आरम्भ किया जाना है।

18. प्रारम्भिक अन्वेषण रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना—आयोग यथास्थिति महानिदेशक अथवा आयोग के किसी अधिकारी को प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा करके उसने समय के भीतर जो वह नियत करे रिपोर्ट (पांच प्रतियों के अतिरिक्त उतनी प्रतियां और जितनी की प्रतियां की संख्या है) प्रस्तुत करने का निवेदन करते हुए आदेश देगा।

परन्तु आयोग महानिदेशक अथवा अन्वेषण करने वाले आयोग के अधिकारी के अनुरोध करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय को बढ़ा सकेगा।

19. प्रारम्भिक अन्वेषण की रिपोर्ट पर कार्रवाई— (1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम 1970 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए आयोग जांच के किसी भी प्रक्रम पर यथास्थिति महानिदेशक अथवा आयोग के किसी अधिकारी द्वारा एकत्र की गई जानकारी अथवा अन्य सामग्री को लेखबद्ध कर सकेगा।

परन्तु आयोग रिपोर्ट जानकारी अथवा सामग्री के ऐसे भाग अथवा भागों को अभिलेखबद्ध नहीं करेगा जिनका प्रकट किया जाना आयोग की राय में जांच से सुसंगत या लोकहित में नहीं है।

(2) जहां पर कोई पक्षकार अभिलेखबद्ध रिपोर्ट का खंडन करना चाहता है वहां पर महानिदेशक उत्तर देने का हकदार होगा।

20. महानिदेशक इत्यादि द्वारा अतिरिक्त अन्वेषण करना—

(1) जहां विनियम 18 के अधीन प्रस्तुत की गई महानिदेशक अथवा आयोग के किसी अधिकारी की रिपोर्ट का परिशीलन करने पर आयोग की यह राय है कि अतिरिक्त अन्वेषण आवश्यक है वहां पर वह महानिदेशक अथवा आयोग के ऐसे अधिकारी को ऐसा और अन्वेषण जो वह आवश्यक समझे करने और अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) जहां यथास्थिति विनियम 18 अथवा इस विनियम के उपविनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अथवा दोनों का परिशीलन करने पर आयोग की यह राय है कि सभी अभिकथनों अथवा इनमें से किसी के बारे में जांच की सूचना जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है वहां वह यथास्थिति सभी अभिकथनों अथवा उनमें से किसी के बारे में कार्यवाहियों को बंद कर सकेगा।

परन्तु जहां पर अन्वेषण धारा 10 या 36ख अथवा 31 के अधीन प्राप्त परिवाद निवेदन अथवा आवेदन के आधार पर किया गया है वहां पर आयोग यथास्थिति परिवादी को संबंधित सरकार को अथवा महानिदेशक को, परन्तु धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (4) अथवा धारा 36 ख के खंड (घ) के अन्तर्गत आने वाले परिवादी को नहीं सभी अभिकथनों अथवा उनमें से किसी के बारे में कार्यवाहियों को बन्द करने का आदेश देने से पहले सुने जाने का अवसर देगा।

परन्तु आगे यह और कि धारा 60 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन जांच करने प्रयोजन के लिए उस रजिस्टर्ड उपभोक्ता संगम अथवा व्यापारिक संगम या उपभोक्ता को जिसने वह परिवाद फाइल किया है और जिसके आधार पर अन्वेषण किया गया है प्रारम्भिक अन्वेषण रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जा सकेगी।

21. प्रारम्भिक अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर जांच— जहां पर यथास्थिति विनियम 18 अथवा विनियम 20 के उपविनियम (1) या दोनों के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात आयोग की यह राय है कि किसी अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार के संबंध में जांच अवश्य की जाए वहां पर वह ऐसा आदेश होगा। ऐसी जांच इन विनियमों के अध्याय 9 और 10 में अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

22. प्रारम्भिक अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार के संबंध में जांच—जहां स्थिति विनियम 18 अथवा विनियम 20 के उपविनियम (1) या दोनों के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात आयोग की प्रथम दृष्टया यह राय है कि धारा 10 के खंड (ख) के अधीन किसी व्यापारिक व्यवहार की जांच की जाएगी तो अध्याय 9 में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के संबंध में दी गई प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित अपनाई जाएगी। जांच के पश्चात आयोग अधिनियम की धारा 31 में यथा उपबंधित के अनुसार कार्यवाही करेगा।

अध्याय 3

महानिदेशक के कर्तव्य और कृत्य

23. उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष आयोग का प्रतिनिधित्व करना—धारा 55 के अधीन अपील की दशा में अथवा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अपील करने की इजाजत के लिए दिए गए आवेदन की दशा में अथवा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 32 के अधीन रिट याचिका की दशा में उन मामलों के सिवाय जहां पर महानिदेशक ने स्वयं अपील फाइल की है अथवा आयोग के आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत के द्वारा अपील फाइल की है महानिदेशक यथास्थिति उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष आयोग का प्रतिनिधित्व करेगा।

24. महानिदेशक के समक्ष आवेदन का फाइल किया जाना—धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किये जाने वाले आवेदन के साथ उसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां सहित उतनी अतिरिक्त प्रतियां फाइल की जायेंगी जितनी कि प्रत्यर्थियों की संख्या है।

25. आयोग से निदेश प्राप्त करने के लिये महानिदेशक द्वारा आवेदन—जहां पर महानिदेशक धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन को निपटाने के लिये आयोग से कोई विशेष निवेश प्राप्त करना चाहता है, वहां पर वह उस आशय का एक आवेदन उसकी 4 प्रतियों सहित करेगा और उस आवेदन में ऐसी जानकारी देगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो नीचे वर्णित हैं:—

- (क) संबंधित पक्षकार के आवेदन की एक प्रति,
- (ख) करार की प्रति (चार प्रतियों में), और
- (ग) आवेदन पर महानिदेशक की टीका-टिप्पणी।

26. आयोग द्वारा महानिदेशक के आवेदन का निपटारा—
विनियम 25 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, यदि आयोग आवश्यक समझे तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर दे सकेगा। ऐसी कार्यवाहियों में महानिदेशक की भी सुनवाई की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये सुनवाई की तारीख के संबंध में उसे सूचना भेजी जायेगी।

अध्याय 4

आयोग के अधिकारियों द्वारा जांच और अन्वेषण

27. जांच का तरीका—(1) विनियम 17, विनियम 18, विनियम 19 और विनियम 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग किसी भी समय सीधे महानिदेशक को या अपने किसी ऐसे एक या अधिक अधिकारियों को, जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, यह निवेश दे सकेगा कि वह ऐसे किन्हीं व्यापारिक व्यवहारों की बाबत जो एकाधिकार, अवरोधक या अनुचित व्यापारिक गठित करते हैं या जो किसी व्यापार में विद्यमान एकाधिकार अवरोधक या अनुचित व्यापारिक व्यवहार में सहायक है या जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उनका व्यवहार किसी उत्पादक वितरक, व्यवहारी, कृषक, प्रसंस्करणकर्ता, खनक या विनिधानकर्ता द्वारा किया जा रहा है अथवा अधिनियम के अध्याय III, अध्याय IV, अध्याय V और अध्याय 6 अथवा धारा 61 के अधीन किसी आवेदन या निर्देश की बाबत, अध्ययन और अन्वेषण करें और रिपोर्ट या जानकारी दें और इस प्रयोजन के लिये आयोग महानिदेशक को या आयोग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को कोई निवेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा और ऐसा समय नियत कर सकेगा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी या जानकारी दी जायेगी। यदि आयोग को यह प्रतीत हो कि ऐसी रिपोर्ट या जानकारी अपर्याप्त है तो आयोग और या अनुपूरक रिपोर्ट या जानकारी के लिये निवेश दे सकेगा।

(2) विनियम 19 और 20 के उपबन्ध, उपविनियम (1) के अधीन यथास्थिति, दी गई रिपोर्ट या एकत्र की गई जानकारी, सामग्री और साक्ष्य, यदि कोई है, को उनके संबंध में किये जाने के लिये सुस्थापित किसी कार्यवाही, के प्रयोजन के लिये लागू होंगे।

अध्याय 5

सरकार द्वारा अधिनियम के अध्याय 3 और अध्याय 3क के अधीन निर्देश की प्रक्रिया

28. अधिनियम की धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 27 और धारा 27क के अधीन प्राप्त निर्देश—

(1) जहां अधिनियम की धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 27 और धारा 27क के अधीन आयोग को केन्द्रीय सरकार का कोई निवेश प्राप्त होता है, वहां आयोग निर्देशों से संबंधित विशिष्टियों को संक्षेप में ऐसे दैनिक

समाचार पत्रों में, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सूचना के रूप में प्रकाशित कर सकेगा जिनमें प्रस्थापना के बारे में ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में उल्लिखित की जाये टिप्पणियां आमंत्रित की जायेंगी। टिप्पणियां चार प्रतियों में भेजी जायेंगी और भेजने वाला व्यक्ति यह कथित करेगा कि क्या सूचित की गई प्रस्थापना के संबंध में आयोग के समक्ष की जाने वाली सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लेना चाहता है।

(2) अधिनियम की धारा 27 या धारा 27क के के अधीन निर्देश की दशा में, आयोग ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अपनी अंतिम राय बनायेगा। इसके पश्चात् वह संबंधित उपक्रम के स्वामी को निर्देश और अपनी अंतिम राय की एक प्रति देगा। संबंधित उपक्रम (उपक्रमों) का स्वामी अंतिम राय के के बारे में अपने आप्क्षेपों और/या सुझावों का एक कथन उसने समय के भीतर फाइल कर सकेगा जितना समय आयोग प्रत्येक मामले के लिये नियत करे।

(3) आयोग आवेदक, संबंधित सरकारी विभाग और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी विशिष्टियां और जानकारी संग्रहित हुए उन्हें पत्र लिख सकेगा जो आयोग की राय में आयोग को प्राप्त निर्देश से सुसंगत हो। आयोग को ऐसे पत्रों के उत्तर चार प्रतियों में दिये जायेंगे।

(4) आयोग आवेदक, संबंधित उपक्रम (उपक्रमों) के स्वामी, किसी सरकारी अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विचार-विमर्श के लिये बुला सकेगा जो वह जांच के लिए आवश्यक समझे।

(5) आयोग ऐसे स्थापन को जिसके अन्तर्गत आवेदक या संबंधित उपक्रम के स्वामी का स्थापन भी है, देखने के लिये जा सकेगा और उनके प्रतिनिधियों के साथ उस दशा में विचार-विमर्श कर सकेगा। जब आयोग का यह विचार हो कि इस प्रकार देखने के लिये जाना और विचार-विमर्श जांच के लिये लाभप्रद होगा।

(6) आयोग निर्देश से सुसंगत जांच और विचार विमर्श के लिये अपने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे स्थानों पर और ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिये भेज सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे और वह ऐसे अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा।

(7) आवेदक, संबंधित उपक्रमों के स्वामी, उन व्यक्तियों को, जो अपनी टीका-टिप्पणी भेज चुके हैं और जिन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है और ऐसे अन्य

व्यक्तियों को, जिनके बारे में आयोग अध्याधारिक करे, सार्वजनिक सुनवाई के लिये नियत तारीख से 21 दिन पहले सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित किया जायेगा। वे व्यक्ति, जो अपनी टीका-टिप्पणी और सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने की अपनी इच्छा के बारे में सूचना भेज चुके हैं, सार्वजनिक सुनवाई की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले आयोग के पास एक कथन फाइल करेंगे जिसमें यह निवेदन किया जायेगा कि वे सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेना चाहते थे।

(8) अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग उन व्यक्तियों की सुनवाई करेगा जिन्हें उपविनियम (7) के अधीन सार्वजनिक सुनवाई की सूचना भेजी जाती है। आयोग यदि आवश्यक समझता है तो साक्षियों की, जिनके अन्तर्गत विशेषज्ञ भी हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, परीक्षा करेगा। इस प्रकार परीक्षा किये गये व्यक्तियों की, आयोग के विवेकानुसार किसी भी ऐसे पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षा करने दी जायेगी, जिसे सार्वजनिक सुनवाई की सूचना भेजी गई है।

(9) इस विनियम के अधीन आयोग द्वारा की जाने वाली जांच में, केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की हकदार होगी जिसे वह प्रतिनियुक्त करे। संबंधित व्यक्ति या तो स्वयं सुने जायेंगे या उनका किन्हीं ऐसे काउन्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा जिसे उन्होंने अपनी ओर से कार्य करने के लिये विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया है।

अध्याय—6

अधिनियम की धारा 10 के खंड (ख) और धारा 37 की उपधारा (4)

29. अधिनियम की धारा 31 के अधीन निर्देश पर अथवा एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार की जांच अधिनियम की धारा 10 के खंड (ख) के अधीन अपनी स्वयं की जानकारी या इस्तिस्ना पर आयोग यह निर्देश देगा कि जांच आयोग के निर्देशक (अन्वेषण और प्रवर्तन) द्वारा की जायेगी और प्रारम्भिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह जांच करेगा और इस प्रयोजन के लिये यथास्थिति इन विनियमों के अध्याय 9 के अधीन दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ऐसी जांच के पश्चात् आयोग धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा।

अध्याय—7

अधिनियम की धारा 24, धारा 27 और धारा 27क और धारा 61 के अधीन निर्देश

30. जहां केन्द्रीय सरकार आयोग से यह अपेक्षा करती है कि वह धारा 61 के अधीन रिपोर्ट दे या उससे धारा 24, धारा 27 और धारा 27क के अधीन परामर्श करती है वहां आयोग अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनिश्चय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार कर सकेगा। ऐसे मामले में रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिये आयोग ऐसे विशेषज्ञों को नियोजित कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

अध्याय—8

न्यूनतम पुनर्विक्रय मूल्य को बनाये रखना (छूट) आवेदन

31. धारा 39 से 40 तक छूट देना—महानिदेशक या हितवद्ध कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो धारा 39 और धारा 40 के प्रवर्तन से छूट के लिये धारा 41 के अधीन आयोग को निर्देश करना चाहता है, वह निम्नलिखित बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए लिखित रूप में आवेदन करेगा :—

(क) उस हित की प्रकृति जिसके लिये आवेदक दावा करता है और जो उसे निर्देश करने का हकदार बनाता है,

(ख) उपवर्ग, यदि कोई है, दर्शाते हुए, माल का वह वर्ग जिससे उसका संबंध है,

(ग) व्यापार नाम (नामों) अथवा व्यापार चिह्न जिससे या जिनसे बाजार में माल की पहचान की जाती है,

(घ) उस वर्ग के माल का, जिसके लिये आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है, कारबार करने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम और पते जहां तक कि आवेदन ऐसी जानकारी एकत्र कर सकता है,

(ङ) धारा 41 की उपधारा (1) का (के) वह (वे) खंड जिस (जिन) पर किये गये आवेदन के लिये निर्भर किया गया है और उसके समर्थन के लिये कारण।

32. आवेदन में आवश्यक माध्य का समावेश—

विनियम 31 में निर्दिष्ट आवेदन में उल्लिखित तथ्यों माध्य द्वारा समर्थित होंगे और उनको सत्यापित करना होगा।

33. एक से अधिक व्यक्ति द्वारा आवेदन—जहां एक से अधिक व्यक्ति ऐसे समरूप वर्ग के माल का जिसके लिये धारा 41 के अधीन छूट मांगी गई है, कारबार करते हैं, वहां आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

34. सामूहिक आवेदन—जहां मांग के जिन अनेक वर्गों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें आपस में निकट संबंध है तो ऐसे अनेक वर्गों के माल के लिये सामूहिक आवेदन

किया जा सकेगा। तथापि यदि गये सामूहिक आवेदन पर विचार करने के पश्चात् आयोग की यह राय हो कि यह आवश्यक और वांछनीय है कि आवेदन अलग-अलग हों तो वह आवेदकों को अलग-अलग आवेदन करने के लिये कह सकेगा।

35. माल के प्रत्येक वर्ग के लिये अलग-अलग आवेदन—जहाँ माल के जिन एक से अधिक वर्ग के लिये छूट की मांग की गई है और उनका आपस में निकट संबंध नहीं है वहाँ ऐसे वर्ग के माल के लिये अलग-अलग आवेदन किया जायेगा।

36. सूचना आदि का जारी किया जाना—

(1) आवेदन की प्राप्ति पर यदि सचिव की राय है कि आवेदन में प्रथम दृष्टया कोई सार नहीं है तो वह उसे प्रारम्भिक सुनवाई के लिये आयोग के समक्ष रख सकेगा और आवेदकों को ऐसी सुनवाई की तारीख सूचित करेगा। आयोग आवेदकों की सुनवाई के पश्चात् आवेदन को प्रारम्भ में ही नामंजूर कर सकेगा।

(2) सचिव उन आवेदनों के बारे में, जो प्रारम्भ में ही नामंजूर नहीं किये जाते हैं, सभी संबद्ध पक्षकारों को सूचना देगा और ऐसे दैनिक समाचार-पत्र या समाचार-पत्रों में जिनका आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिश्चय करे, विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक सूचना भी देगा। सूचना में सुसंगत बातों का, जिनके अन्तर्गत उस वर्ग या वर्गों के माल भी है, जिनके लिये आवेदन किया गया है, संक्षेप में उल्लेख किया जायेगा।

(3) सचिव आवेदन की विषय-वस्तु के संबंध में कार्रवाई करने वाले मंत्रालय या विभाग के सचिव को भी सूचना की एक प्रति यह सूचित करने हुए भेजेगा कि मंत्रालय अथवा विभाग आवेदन की विषय-वस्तु की बाबत अपनी टीका-टिप्पणी, यदि वह ऐसा चाहे तो आयोग को भेज सकेगा।

37. अभ्यावेदन—निर्देश का समर्थन अथवा विरोध करने वाले अभ्यावेदन समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर फाइल किये जायेंगे और उसमें अभ्यावेदन करने वाले पक्षकार के हित भी प्रकृति का और इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि क्या वह सूचना से संबंधित सभी माल या उसमें से किसी की बाबत न्यूनतम पुनर्विक्रय मूल्य को बनाये रखने का समर्थन करता है या विरोध करता है। ऐसे अभ्यावेदन विनियम 58 की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे और विनियम 49 में विहित रीति में सत्यापित किये जायेंगे।

38. प्रारम्भिक सुनवाई—(1) विनियम 37 के अधीन अभ्यावेदन दाखिल करने के लिये समय-सीमा की समाप्ति

के पश्चात् आयोग प्रारम्भिक सुनवाई के लिये तारीख नियत करेगा। आवेदक, जिसने आयोग के समक्ष निर्देश दाखिल किया था, मामले का कथन करेगा और मोटे तौर पर यह बतायेगा कि आयोग के समक्ष वह क्या निवेदन करेगा। इस सुनवाई के दौरान आवेदक पर उन अभ्यावेदनों के प्रतियों की तामील की जायेगी जो सूचना के उत्तर में प्राप्त हुए थे और वह उसके तामील के 14 दिन के भीतर अपना उत्तर फाइल करेगा।

(2) यदि प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान आयोग को यह प्रतीत होता है कि निर्देश में की गई प्रार्थना और मामले की परिस्थितियों सारभूत रूप से वैसी ही है जिन पर आयोग के समक्ष उन पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में विचार किया गया है जो निपटाई जा चुकी हैं, तो वह निर्देश के संक्षेपतः निपटाए जाने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(3) जहाँ आवेदक या कोई प्रत्यर्थी आदेश के लिये आयोग को आवेदन करता है कि आयोग के समक्ष संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों को समेकित किया जाये और उनकी सुनवाई एक साथ की जाये, वहाँ दोनों कार्यवाहियाँ, यदि आयोग ऐसा निर्देश करता है तो समेकित की जा सकेंगी और उनकी एक साथ सुनवाई की जा सकेगी।

39. किसी अन्य हितवद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल आवेदन के बारे में महानिदेशक आदि द्वारा अन्वेषण:—

(1) विनियम 38 में उल्लिखित सुनवाई के पश्चात् और प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् आयोग के मामले को, यदि वह आवश्यक समझे तो महानिदेशक या आयोग किसी अन्य अधिकारी को ऐसी रीति में आदेश कर सकेगा, जैसा वह निर्दिष्ट करे।

(2) महानिदेशक अथवा आयोग का कोई अन्य अधिकारी जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, अन्वेषण के लिए किए गए निर्देश से 90 दिन के भीतर अथवा आयोग द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर आयोग को रिपोर्ट देगा जिसमें उसके अन्वेषण के निष्कर्ष होंगे।

40. निर्देश—महानिदेशक अथवा आयोग के किसी अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् और विनियम 37 के अनुसार प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान इन कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और प्राप्त अभ्यावेदनों में अंतर्निहित निवेदनों तथा आवेदक द्वारा फाइल किए गए उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् आयोग—

(क) अवधारित करेगा कि जिस व्यक्तियों ने सार्वजनिक सूचना के उत्तर में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन किया है, उनमें से किसे आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने दिया जाए या किसको कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने दिया जाए,

(ख) आदेश कर सकेगा कि उसके समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने वाले किन्हीं या सभी व्यक्तियों का

ऐसे एक ही प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का, जिसे वह उचित समझे, निर्देश करे।

ग) ऐसे अन्य निर्देश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

- (1) सुनवाई की सूचना, अथवा किसी अभ्यावेदन, जवाब अथवा उत्तर का संशोधन,
- (2) अतिरिक्त और बेहतर विशिष्टियों का परिदान,
- (3) परिप्रश्नों का परिदान,
- (4) किन्हीं तथ्यों अथवा दस्तावेजों की स्वीकृति,
- (5) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण अथवा अतिरिक्त प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण,
- (6) किन्हीं दस्तावेजों की साक्ष्य स्वीकृति,
- (7) साक्ष्य देने का ढंग
- (8) किसी साक्ष्य का लिया जाना और अभिलिखित किया जाना जिसके अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए कमिशनर की नियुक्ति करना भी है,
- (9) किसी माल का उत्पादन या प्रदाय करने में, या माल के विनिर्माण की कोई प्रक्रिया लागू करने में, किसी वगैरे के माल के बारे में लागू का अन्वेषण और वह रीति जिसमें ऐसे अन्वेषण का परिणाम अंतिम सुनवाई में आयोग के समक्ष लाया जाना है,

41. सुनवाई की सूचना की तामील—सचिव सुनवाई के लिए नियत तारीख सूचित करने हुए ऐसी नियत तारीख से कम से कम 21 दिन पहले सूचना की एक प्रति की आवेदक और व्यक्तियों पर लिखित रूप में तामील करेगा जो विनियम 40 की मद संख्या (क) और (ख) में दिए गए निर्देशों के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार हैं और ऐसी सूचना के साथ उन व्यक्तियों की दशा में, जो इन निर्देशों के आधार पर कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार होंगे, निर्देश की एक प्रति या प्रतियां लगी होंगी।

42. अंतिम सुनवाई—इन निर्देश की बाबत सुनवाई विनियम 70 के अनुसार होगी।

43. अंतर्वर्ती आदेश—जहां निर्देश के संक्षेपतः अवधारण के लिए या समेकन के लिए विनियम 38 के अधीन कोई निर्देश दिया गया है वहां आयोग यदि उसका यह समाधान करता है कि निर्देश के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों और उन तथ्यों और परिस्थितियों में, जिन पर विचार किया गया था, कोई सारभूत अंतर नहीं है तो सुनवाई में—

- (क) साक्ष्य की सुनवाई के बिना या ऐसे साक्ष्य पर जिसे वह ठीक समझे, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, आवेदन पर संक्षेपतः आदेश कर सकेगा, और

(ख) आदेश द्वारा कोई ऐसा निर्देश दे सकेगा जिसे वह अधिनियम की धारा 41 के अधीन उस दशा में दे सकता था जब विवादक का अवधारण साधारण तौर पर अंतिम सुनवाई के पश्चात् किया जाता या निर्देश देने वाले ऐसे आदेश को तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक कि कार्यवाहियों में के सभी अन्य विवादकों का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

44. अंतिम आदेश—आवेदकों और उन व्यक्तियों की जिन्होंने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन दायित्व किए और जिन्हें कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया गया है सुनवाई के पश्चात् और ऐसे साक्ष्यों की जिन्हें आयोग बुलाए, परीक्षा करने के पश्चात् वह आवेदन/आवेदनों पर अंतिम आदेश पारित करेगा। ऐसे आदेश भी सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और आयोग की मुद्रा लगी एक प्रति भी आवेदक पर और कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात अन्य व्यक्तियों पर तामील की जाएगी।

अध्याय-9

अधिनियम की धारा 37 के अधीन कार्यवाहियां

45. धारा 10 (क) (1) के अधीन परिवाद (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (1) के अधीन परिवाद में परिवाद के वे तथ्य अंतर्विष्ट होंगे जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गठित करते हैं।

(2) किसी व्यापार संगम अथवा किसी रजिस्टर्ड व्यापार संगम द्वारा किए गए परिवाद पर संगम के उस पदाधिकारी द्वारा, जिसे उस संगम में प्रधान द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सत्यापित किया जाएगा। किसी उपभोक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए परिवाद पर उस उपभोक्ता द्वारा विनियम 49 में विहित रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सत्यापित किया जाएगा।

46. सरकार द्वारा निर्देश—धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्देश में उसी प्रकार के तथ्य अंतर्विष्ट होंगे जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गठित करते हैं, और वह निर्देश विनियम 49 में विहित रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

47. महानिदेशक द्वारा आवेदन—महानिदेशक द्वारा धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iii) के तहत किये गये आवेदन — वे तथ्य होंगे जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गठित करते हैं और, यदि यह अधिनियम की धारा 33 के तहत पंजीकरण योग्य किसी करार से संबंधित हो तो, उसमें करार के ऐसे भाग उपवर्णित होंगे जो किये गये परिवाद के तथ्यों की प्रकट करने के लिए आवश्यक हैं और वह विनियम 49 विहित रीति महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ;

48. परिवार, निर्देश आदि की प्रतियां—विनियम 45 से विनियम 47 में यथास्थिति, जिस मूल परिवार-निर्देश अथवा आवेदन के प्रति निर्देश किया गया है उसके साथ उसकी चार प्रतियां आयोग के अभिलेख के लिए और उतनी प्रतिरिक्त प्रतियां लगी होंगी जितनी प्रत्यार्थियों पर और अपने-अपने परिवार निर्देश या आवेदन में निर्दिष्ट हितवद्ध अन्य पक्षकारों पर तामील की जाने के लिए आवश्यक हों।

49. आयोग के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचन आदि का हस्ताक्षरित किया जाना—आयोग के समक्ष फाइल किए जाने वाले मामले से संबंधित सभी परिवार, निर्देश, आवेदन कथन और अन्य अभिवचन पक्षकारों या सम्यक् रूप से उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी। जिस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा वह पैराग्राफ की संख्याओं का उल्लेख करते हुए विनिर्दिष्ट रूप से यह बताएगा कि अपने ज्ञान के आधार पर क्या सत्यापित कर रहा है और प्राप्त सूचना और विश्वास के आधार पर सत्य मानते हुए सत्यापित कर रहा है सत्यापित करने वाले व्यक्ति को यह कथन भरना होगा कि वह किस स्थान और किस तारीख को इसे हस्ताक्षरित कर रहा है।

50. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां—अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के अधीन परिवार निर्देश अथवा आवेदन अथवा सूचना प्राप्त होने पर और अभिलेखगत किसी साक्ष्य अथवा प्रारंभिक अन्वेषण रिपोर्ट यदि कोई है पर विचार करने के पश्चात् अगर आयोग की यह राय है कि जिन व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध विवाद किया गया है उसके/उनके विरुद्ध उपसंजात होने के लिए आदेशिका जारी करने के लिए पर्याप्त आधार है तो ऐसी आदेशिका जारी की जाएगी और इसे "जांच की सूचना" कहा जाएगा।

51. जांच की सूचना—(1) विनियम 50 में विनिर्दिष्ट जांच की सूचना के साथ निम्नलिखित होंगे—

- (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन किसी परिवार की दशा में ऐसे परिवार की एक प्रति
- (2) अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन किसी निर्देश की दशा में ऐसे निर्देश की एक प्रति
- (3) अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन किसी आवेदन की दशा में ऐसे आवेदन की एक प्रति और
- (4) अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन किसी जांच की दशा में उनमें तात्त्विक तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन जिन पर वह सूचना आधारित है अथवा प्रारंभिक अन्वेषण रिपोर्ट अथवा उसके सुसंगत उद्धरण की एक प्रति।

(2) आयोग अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के दो या उससे अधिक उपखंडों के अधीन संयुक्त रूप से एक साथ सूचना जारी करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(3) ऐसी प्रत्येक सूचना में आयोग के समक्ष सुनवाई तारीख और स्थान विनिर्दिष्ट होगा।

52. सूचना अनेकों करारों अथवा व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में हो सकेगी कोई सूचना एक करार या अनेक करारों या एक व्यापारिक व्यवहार या अनेक व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में हो सकती है जो आयोग को आपस में इस प्रकार जुड़े हुए प्रतीत होते हों कि उन पर एक ही कार्यवाही में विचार किया जाना वांछनीय है।

53. सूचना पर आयोग की मुद्रा—सूचना पर आयोग की मुद्रा लगी होगी और वह सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा जब तामील के पश्चात् वह वापस लौटाई जाएगी तब सचिव द्वारा फाइल की जाएगी।

54. सूचना की तारीख—विनियम 57 के अध्याधीन रहते हुए आयोग सूचना की प्रति को ऐसे पक्षकारों पर तामील कराएगा जैसा आयोग विशिष्ट करे और उन पक्षकारों में से ऐसे पक्षकार जैसा आयोग निर्देश करे कार्यवाहियों में प्रत्यर्था होंगे।

55. व्यापार संगम पर सूचना की तामील—आयोग यदि वह ठीक समझे तो सूचना की एक प्रति की तामील किसी ऐसे व्यापार संगम पर कर सकेगा जिसके सदस्य या जिसका कोई सदस्य किसी करार का पक्षकार है या जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वे किसी व्यापारिक व्यवहार के दोषी हैं। जिसका सूचना से संबंध है और व्यापार संगम यदि आयोग ऐसे निर्देश करे तो संगम के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियम 57 के अधीन किसी आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यवाहियों में प्रत्यर्था बनाए जा सकेंगे।

56. जांच की सूचना और आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रकाशन—

1. आयोग द्वारा की गई जांच और आयोग द्वारा पारित आदेशों की बाबत संक्षिप्त विशिष्टियां सचिव द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से तथा ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकेंगी जैसा आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश करें।

(2) सचिव ऐसी रीति में जैसे वह ठीक समझे अथवा जैसा आयोग निर्देश करे प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर सकेगा।

57. व्यक्ति जिनका सामान्य हित है—(1) जहां सामान्य हित रखने वाले कई व्यक्ति हों चाहे वे परिवारी या प्रत्यर्था के रूप में हों अथवा ऐसे पक्षकार के रूप में जो जिन पर विनियम 50 विनियम 53 विनियम 54 अथवा विनियम 55 के अधीन सूचना की तामील की गई है वहां आयोग आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट परिवारी प्रत्यर्था या पक्षकार सामान्य हित रखने वाले सभी व्यक्तियों

की ओर से या उनके फायदे के लिए कार्यवाही में उपसंजात होंगे और आयोग ऐसी दशा में सामान्य हित रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को कार्यवाही की सूचना या तो वैयक्तिक तामील करके या जहाँ ऐसे व्यक्ति जिन पर तामील की जानी है अधिक संख्या है अथवा किसी अन्य कारण से ऐसी वैयक्तिक तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहाँ सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा जैसा आयोग प्रत्येक मामले में निर्देश दे देगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए कोई पक्षकार कार्यवाहियों में उपसंजात होता है, कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा।

(3) ऐसे मामलों में आयोग यह अवधारित करेगा कि किसी सार्वजनिक विज्ञापन या वैयक्तिक तामील का खर्चा कौन उठाएगा।

58. पक्षकारों का उपसंजात होना—(1) ऐसा प्रत्यर्थी जिस पर सूचना की तामील की गई है और जो यह चाहता है कि कार्यवाहियों में उसकी सुनवाई की जाए, सूचना में विनिर्दिष्ट सुनवाई की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व आयोग के कार्यालय में पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित एक ज्ञापन सचिव को, जिसकी एक प्रति महानिदेशक को भी भेजी जाएगी, परिदत्त करके उपसंजात होगा जिसमें वह यह उपदर्शित करेगा कि वह कार्यवाहियों में स्वयं को सुनाना चाहता है और उसमें उसके अधिवक्ता या अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, निवास स्थान का और उसके कार्यालय का पूरा पता होगा और जो आदेशिका की तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है।

(2) वह अधिवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसका प्रत्यर्थी ने नाम दिया है, उपसंजात होने के समय वकालतनामा/मुस्तारनामा दाखिल करेगा।

स्पष्टीकरण—प्राधिकृत प्रतिनिधियों या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, भारतीय लागत तथा संकर्य लेखापाल संस्थान का अथवा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होगा अथवा वह व्यक्ति होगा जो स्नातकोत्तर हो, अथवा वाणिज्य में अथवा अर्थशास्त्र अथवा प्रबंध में उच्च योग्यता प्राप्त हो और जिसमें कार्यालय और निवास का पूरा पता देना होगा।

59. सूचना का उत्तर—(1) प्रत्येक ऐसा प्रत्यर्थी, जो उपसंजात हुआ है, उपसंजात होते समय सूचना का उत्तर (प्रत्यर्थियों के संख्या के अतिरिक्त 5 प्रतियों सहित) सचिव को परिदत्त करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) अधिनियम की धारा 38 के प्रत्येक परिस्थितियों की विनिर्दिष्टियाँ जिन पर वह निर्भर करना चाहता है और

(ख) उसके द्वारा अभिकथित उन तथ्यों और मामलों की विनिर्दिष्टियाँ जो उसे धारा 38 का अवलंब लेने के लिए हकदार बनाती हैं।

(2) जहाँ प्रत्यर्थी अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य के रूप में किन्हीं दस्तावेजों पर (जो उसके कब्जे या शक्ति में

हो या न हो) निर्भर करता है, वहाँ वह उत्तर में जोड़ी या उसके साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में ऐसे दस्तावेजों की प्रविष्टि करेगा। जहाँ ऐसा कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी के कब्जे अथवा शक्ति में नहीं है, वह यदि संभव हुआ, तो वह यह कथित करेगा कि वह किसके कब्जे या शक्ति में है। प्रत्यर्थी अवलंब लिए गए दस्तावेजों की सूची के साथ जांच की सूचना के उत्तर की प्रति भी परिवादी (चाहे वह व्यक्ति है अथवा रजिस्टर्ड उपभोक्ता संगत या व्यापार संगत है) भेजेगा अथवा परिदत्त करेगा।

(3) वह दस्तावेज, जिसे उपानियम (2) में निर्दिष्ट सूची में प्रविष्टि किया जाना चाहिए था किन्तु उसे इस प्रकार से प्रविष्टि नहीं किया गया था आयोग की इजाजत के बिना प्रत्यर्थी की ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) सचिव यथाशीघ्र महानिदेशक अथवा परिवादी सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को, अगर प्रत्यर्थी द्वारा उनमें से किसी को प्रतियाँ परिदत्त नहीं की गई हैं, प्रति (प्रतियाँ) देगा।

60. महानिदेशक द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण करने की सूचना :—प्रत्येक प्रत्यर्थी महानिदेशक से उसके संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सात दिन के भीतर उन दस्तावेजों को या उनमें ऐसे दस्तावेजों को जो सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उसके निरीक्षण के लिए पेश करेगा और उसे उनकी प्रति लेने देगा।

परन्तु इसमें की कोई भी बात उक्त दस्तावेजों में से किसी के लिए विशेषाधिकार का दावा करने के प्रत्यर्थी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

61. अभिवचनों को फाइल करना—उत्तर के पश्चात् कोई भी अभिवचन आयोग की इजाजत से ही ऐसे निबंधनों पर जिन्हें आयोग ठीक समझे, फाइल किया जाएगा अन्यथा नहीं किन्तु आयोग किसी भी पक्षकार से किसी भी समय अभिवचन या प्रत्युत्तर या अनुपूरक अभिवचन की अपेक्षा कर सकेगा और उसे फाइल करने के लिए समय नियत कर सकेगा।

62. आयोग सम्पूर्ण अभिवचन को अथवा उसके किसी भाग को काट सकेगा आयोग किसी पक्षकार के आवेदन पर सम्पूर्ण उत्तर, प्रत्युत्तर, अभिवचन या अनुपूरक अभिवचन या उसके किसी भाग को, जिसके बारे में आयोग को यह ज्ञात हो कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 6 के नियम 16 के उपबंधों के अनुसार काटे जाने के दायित्वधीन है काट सकेगा और ऐसी दशा में उत्तर, प्रत्युत्तर अभिवचन या अनुपूरक अभिवचन परिदत्त करने के लिए अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा।

63. कार्यवाहियों में संशोधन—(1) आयोग किसी भी समय किसी भी कार्यवाहियों में की, जिसमें जांच की सूचना भी सम्मिलित है किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा और ऐसी कार्यवाहियों द्वारा उठाए गए या उन पर अवलंबित वास्तविक प्रश्न या विवादक के अवधारण के प्रोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

(2) आयोग किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह जांच की सूचना के अपने उत्तर, प्रत्युत्तर, अभिवचन या अनुपूरक अभिवचन को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायसंगत हो परिवर्तित करे या संशोधित करे और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो वास्तविक विवादग्रस्त प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

64. पक्षकारों का संयोजन—कार्यवाहियों का कोई पक्षकार आयोग को (आवेदन की 4 अतिरिक्त प्रतियों सहित) किसी भी समय इस आदेश के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से पक्षकार नहीं है, कार्यवाही के पक्षकार के रूप में जोड़ा जाए, आवेदन कर सकेगा और आवेदन की सूचना सभी अन्य पक्षकारों और उन व्यक्तियों को देगा जिनकी जोड़े जाने के लिए आवेदन किया गया है।

(2) आयोग कार्यवाहियों में के किसी भी प्रक्रम में या तो स्वयं अपने आप अथवा कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे निबंधनों पर जो आयोग को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि अनुचित तौर पर संयोजित किसी पक्षकार का नाम काट दिया जाए जिसे ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था अथवा जिस भी आयोग के सामने उपस्थिति इस दृष्टि से आवश्यक हो कि आयोग कार्यवाहियों में अंतर्बलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा कर सकेगा।

(3) जहां कोई पक्षकार जोड़ा जाता है या किसी पक्षकार का नाम काटा जाता है वहां जब तक आयोग अन्यथा निर्दिष्ट न करे अभिवचन को इस प्रकार संशोधन किया जाएगा जैसा आवश्यक हो।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश के उपबंध इन कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(5) कोई भी परिवादी, आवेदक अथवा सरकारी प्राधिकारी जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (i) से (iii) के अधीन यथास्थिति परिवाद आवेदन अथवा निर्देश करता है, एक पक्षकार होगा और उसे अभिवचन फाइल करने, सुने जाने का हकदार होगा। वह किसी आवेदन, यदि कोई है, अभिवचन की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा जो जांच की कार्यवाहियों के दौरान महानिदेशक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल की गई हो। मगर वह आवेदन करता है तो आयोग अपने स्वयंसेवक से किसी सूचना के बारे में कार्यवाहियों की सुनवाई कर सकेगा। यदि आयोग द्वारा निर्देश किया जाता है तो सचिव विनियम 45, विनियम 46, विनियम 47, विनियम 58, विनियम 59 और विनियम 63 के अधीन उसके पास फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रतिलिपि उसे दे सकेगा।

65. निर्देशों के लिए आवेदन—(1) आयोग सुनवाई की तारीख को या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा

किए गए आवेदन पर निम्नलिखित विषयों के बारे में ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे वह उचित समझे—

- (क) सुनवाई की सूचना या किसी अभ्यावेदन, जवाब अथवा उत्तर का संशोधन,
- (ख) अतिरिक्त और बेहतर विशिष्टियों का परिदान,
- (ग) परिप्रश्नों का परिदान,
- (घ) किन्हीं तथ्यों या दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना,
- (ङ) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण या अतिरिक्त प्रकटीकरण और उनको निरीक्षण,
- (च) किसी दस्तावेज का साक्ष्य में ग्रहण किया जाना,
- (छ) साक्ष्य देने का ढंग,
- (ज) किन्हीं घटनाओं को लेना और उनको अभिलिखित किया जाना, जिसके अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए कमीशनर की नियुक्ति भी है,
- (झ) किसी माल का उत्पादन या प्रदाय करने में अथवा माल के विनिर्माण की कोई प्रक्रिया लागू करने में माल के किसी वर्ग की बाबत खर्चों का अन्वेषण और वह रीति जिससे ऐसे अन्वेषण का परिणाम अंतिम सुनवाई के समय आयोग के समक्ष लाया जाना है, और
- (ञ) कोई अन्य विषय जो जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित समझा जाए।

(2) किसी ऐसी जांच में, जहां विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाधकों की विरचना की गई है और यथास्थिति, महानिदेशक, परिवादी या निर्देश करने वाले व्यक्ति ने उन दस्तावेजों की सूची दाखिल नहीं की है, जिन पर वह निर्भर करता है, वहां वह विवाधकों की विरचना की तारीख को या ऐसे समय के भीतर जैसा आयोग निर्देश करे, सूची दाखिल करेगा।

66. किसी पक्षकार द्वारा जांच की कार्यवाहियों के दौरान दस्तावेजों को ग्रहण किया जाए—(1) जांच का कोई भी पक्षकार जांच के दूसरे पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह जांच की सूचना की तारीख के 15 दिन के भीतर जांच से सुसंगत दस्तावेज स्वीकार कर ले।

(2) जहां कोई पक्षकार दस्तावेज स्वीकार करने के लिए उस पर सूचना की तारीख के पश्चात् स्वीकृत करने से अनुचित रूप से उपेक्षा या इंकार करता है, वहां आयोग उसे निर्देश दे सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को प्रतिकर के रूप में खर्चों का संदाय करे।

67. अन्तर्वर्ती आवेदन—उस दशा को जोड़कर जहां इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित किया जाए या आयोग अन्यथा निर्देश दे, प्रत्येक अन्तर्वर्ती आवेदन उसकी विषय वस्तु से संबंधित प्रत्येक अन्य पक्षकार को कम से कम 7 दिन की सूचना देकर किया जाएगा और सूचना में उन निर्देशों

या आदेश की विनिष्टियां दी जाएंगी, जिनके लिए आवेदन किया गया है।

68. तथ्यों का साबित किया जाना—सुनवाई के समय साबित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी तथ्य, अगर स्वीकार नहीं किए गए हैं, निम्न प्रकार से साबित किए जाएंगे :—

(1) अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 19 के अनुसार मौखिक साक्ष्य द्वारा, साक्षियों की परीक्षा और प्रति परीक्षा द्वारा अथवा शपथपत्रों, द्वारा और

(2) दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा जिसके अंतर्गत दस्तावेजों की मूल अथवा अधिप्रमाणित प्रतियां, पुस्तकों की प्रविष्टियां अथवा उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां, अथवा उनकी श्रवणीय फिल्म अथवा उनके वीडियो टेपों के द्वारा।

69. वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा सांख्यिकी जानकारी—कार्यवाहियों से सुसंगत वैज्ञानिक, तकनीकी या सांख्यिकी जानकारी की दशा में, वह विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक या व्यापार, प्रकाश या निर्देश संबंधी कृतियां, जिनमें ऐसी जानकारी दी गई हो, आयोग की अनुज्ञा से पेश करके साबित की जाएगी।

70 अंतिम सुनवाई—अंतिम सुनवाई खुले न्यायालय में की जाएगी :

परन्तु यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि यह लोक हित में है कि सुनवाई या उसके भाग की सुनवाई खुले न्यायालय में नहीं की जानी चाहिए या यह समाधान हो जाता है कि विनिर्माण की श्रुत प्रक्रिया के बारे में या किसी खनिज या अन्य निक्षेपों के होने, न होने या उनकी स्थिति के बारे में या इसी प्रकार के किसी ऐसे पदार्थ के बारे में, जिसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति के विधि सम्मत व्यवसाय हित का सारभूत रूप से नुकसान होने की सम्भावना है, साक्ष्य दिया जा सकता है तो वह आदेश देगा और ऐसे किसी अन्य मामले में जिसमें आयोग को ऐसा करना उचित प्रतीत हो तो आदेश दे सकेगा कि सुनवाई या उसके ऐसे भाग की, जैसा आयोग निर्देश करे, सुनवाई बंद कमरे में की जाए।

71. विवाद्यक का संक्षेपतः अवधारित किया जाना—यदि आवेदन की सुनवाई करने पर आयोग को यह प्रतीत होता है कि करार के सुसंगत उपबंध या करार अथवा किसी व्यापारिक व्यवहार या व्यवहारों से संबंधित कोई अन्य तथ्य या परिस्थितियां, सारभूत रूप से वैसी ही हैं जैसी आयोग के समक्ष पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में उन पर विचार किया गया था तो वह निर्देश दे सकेगा कि विवाद्यक संक्षेपतः अवधारित किए जाने के लिए निर्देशित किया जाए।

72. विवाद्यकों को संक्षेपतः अवधारित किए जाने के लिए निर्देश—जहां विनियम 71 के अधीन कोई निर्देश

दिया गया है, वहां पर यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि करार के सुसंगत उपबंधों या मामले के व्यापारिक व्यवहार अथवा व्यवहारों या परिस्थितियों में करार के उन उपबंधों या उन व्यापारिक व्यवहार अथवा व्यवहारों या परिस्थितियों में, जिन पर पूर्वोक्त कार्यवाहियों में विचार किया गया था, कोई सारभूत अंतर है तो सुनवाई में,—

(क) विवाद्यक, साक्ष्य की सुनवाई के बिना या ऐसे साक्ष्य पर, जिसे वह ठीक समझे, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, संक्षेपतः अवधारित कर सकेगा, और

(ख) आदेश द्वारा कोई ऐसा निर्देश दे सकेगा जिसे वह अधिनियम की धारा 37 के अधीन उस दशा में दे सकता था जब विवाद्यक का अवधारण साधारण तौर पर अंतिम सुनवाई के पश्चात् किया जाना या निर्देश देने वाले ऐसे आदेश को तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक कार्यवाहियों में के सभी अन्य विवाद्यकों का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

73. परिवारों के संबंध में टीका-टिप्पणियों का मंगाया जाना—अधिनियम की धारा 10 (क) (1) अथवा 36 (क) के अधीन परिवार प्राप्त होने पर अथवा अधिनियम की धारा 10 (क) (i) अथवा 36 ख (घ) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर आयोग अपने स्वविवेकानुसार अन्वेषण अथवा जांच संस्थित करने के लिए निर्देश देने के बजाय उस व्यक्ति को सीधे ही परिवार अथवा सूचना को एक प्रति भेज सकेगा, जिसके विरुद्ध वह है, जिसमें उससे यह कहा जाएगा कि वह परिवारी अथवा सूचनाकर्ता द्वारा यथा इच्छित आवश्यक कार्य करने के लिए उसे योग्य बनाने के लिए वह अपनी राय भेजे अथवा अपना पक्ष रखे। उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् अथवा अपनी टीका-टिप्पणी भेजने के लिए नियत किए गए समय की समाप्ति के पश्चात् आयोग अधिनियम अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार परिवार अथवा सूचना पर आगे कार्यवाही कर सकेगा।

74. अंतिम आदेश—परिवारी अथवा आवेदक अथवा निर्देश करने वाली सरकारी प्राधिकारी या महानिदेशक तथा प्रत्यक्षियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जिन्होंने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन फाइल किया है और जिन्हें कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, सुनवाई के पश्चात् आयोग परिवार, आवेदन या निर्देश पर अंतिम आदेश पारित करेगा (ऐसे आदेश की सखि द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और आयोग की मद्रा लगी एक प्रति की परिवारी, आवेदक निर्देश करने वाले सरकारी प्राधिकारी, महानिदेशक और कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्तियों पर तामील की जाएगी।

अध्याय 10

अधिनियम की धारा 36 घ के अधीन कार्यवाही

75. अनुचित व्यापारिक व्यवहारों की जांच—इन विनियमों के अध्याय 9 में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के लिए अभिकथित प्रक्रिया, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 36 घ के अधीन अनुचित व्यापारिक व्यवहार की जांच को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी,—

- (1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (1) से (4) तक के प्रति निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो धारा 36 ख के तत्स्थानी खंड (क) से (घ) तक के प्रति निर्देश है, और
- (2) अधिनियम की धारा 37 के प्रति निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो धारा 36 घ के प्रति निर्देश से है।

अध्याय 11

धारा 12 क और 12 ख के अधीन आवेदन

76. अस्थायी आदेश—अधिनियम की धारा 12 क के अधीन अस्थायी आदेश जारी करने के लिए दिया गया प्रत्येक आवेदन आवेदनकर्ता के एक ऐसे शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा जिसमें वे तथ्य जो एकाधिकार, अवरोधक अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार गठित करते हैं और वे परिस्थितियां जिनके द्वारा यह साबित करने का आशय है कि उक्त व्यापारिक व्यवहार से लोकहित या किसी व्यापारी या व्यापारियों या किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के हित पर सामान्य रूप से प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है, कथित होंगे। आवेदन के साथ पांच अतिरिक्त प्रतियां और प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए एक-एक अतिरिक्त प्रति होगी। आवेदन सचिव के पास दाखिल किया जाएगा जो आवेदन को निपटाने के लिए आयोग के समक्ष रखेगा।

77. प्रतिकर के लिए आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 12ख के अधीन प्रतिकर के लिए दिया गया प्रत्येक आवेदन आवेदनकर्ता के एक ऐसे शपथ पत्र द्वारा, जो इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म में होगा, समर्थित होगा जिसमें अभिकथित एकाधिकार, अवरोधक या अनुचित व्यापारिक व्यवहार के परिणामस्वरूप हुई हानि या नुकसान की विशिष्टियां और परिमाण कथित होगा और उसमें यह भी कथन होगा कि उसने न तो आयोग के समक्ष और न ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 काई 68) के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष पहले कोई आवेदन किया है। इसे यह सचिव के पास दाखिल करेगा जिसके साथ पांच अतिरिक्त प्रतियां और प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए एक-एक अतिरिक्त प्रति होगी।

(2) आयोग अधिनियम की धारा 12 क या धारा 12ख के अधीन कोई आवेदन करने से पूर्व महानिदेशक को अभिकथनों का ऐसा अन्वेषण करने काई जो आवश्यक समझा जाए और उन पर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दे सकेगा।

अध्याय 12

आदेश का संशोधन अथवा प्रतिसंस्करण

78. पुनरीक्षण के लिए आवेदन—अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए आवेदन में उन तथ्यों अथवा कारणों का उल्लेख होना चाहिए कि जिनके कारण वे आवेदन, जिनका पुनरीक्षण चाहा गया है, परिवर्तित किए जाएं, उनमें उपांतरण किया जाए या उन्हें अपास्त किया जाए। उनमें जिस व्यक्ति के पक्ष में वह आदेश किया गया है उस व्यक्ति को तथा महानिदेशक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश को बदला, परिवर्तित, उपांतरित अथवा अपास्त नहीं किया जाना चाहिए।

79. गलती की परिशुद्धि—आयोग को किसी कार्यवाही, कार्यवाहियों के संशोधन, घोषणा या आदेश में की लिपिकीय अथवा, गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलती आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय परिशुद्ध की जा सकेगी और इस बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) धारा 152 और धारा 153 में उपबंध लागू होंगे।

[एफ सं. 8 (41)/एम आर टी पी सी/87]
ह. क. मलिक, संयुक्त निदेशक

प्रारूप

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग,
नई दिल्ली के समक्ष

19—का प्रतिकर आवेदन सं. _____
(आवेदक का नाम और पता)

—आवेदक

जनाम

(प्रत्यर्थी का नाम और पता)

—प्रत्यर्थी

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,
1969 की धारा 12 ख के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन
श्रीमन्

आवेदक निम्नानुसार आवेदन करना चाहता है :—

1. दावों संबंधी संक्षिप्त तथ्य
2. एकाधिकार अवरोधक अथवा
अनुचित व्यापारिक व्यवहार के

संबंध में संक्षिप्त कथन

3. हानि, नुकसानी अथवा क्षति की विशिष्टियाँ और वेय रकम

4. इसी मामले से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अधीन अगर कोई कार्यवाहियाँ हैं, तो उनकी विशिष्टियाँ

प्रार्थना

(निश्चित रकम ब्याज की दर अथवा किसी अन्य मद में की किसी रकम का उल्लेख)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

वर्ष 19 के _____ मास _____ दिन को _____ में इसे सत्यापित किया जाता है।

उपर्युक्त पैराओं की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक :—

1. अनुप्रमाणित शपथपत्र

2. निक्षेप रसीद (अगर लागू होती है) की अनुप्रमाणित फोटो प्रति

शपथपत्र

मैं _____ पुत्र _____
_____ प्रायु _____ वर्ष

निवासी _____
भगवान के नाम पर शपथ लेते हुए/सत्य निष्ठा से निम्न प्रकार प्रतिज्ञा करता हूँ :—

(1) मैंने एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, 1969 अधिनियम की धारा 12 ख के अधीन दिए जाने वाले अपने आवेदन का अध्ययन किया है/यह आवेदन सही है/उपाबंध मूल दस्तावेजों की प्रतियाँ हैं/और मूल दस्तावेजों का सही अनुवाद है।

(2) उपर्युक्त आवेदन ही एकमात्र आवेदन है/उपर्युक्त आवेदन के अतिरिक्त मैंने ऐसा ही एक आवेदन

महानिदेशक अन्वेषण और पंजीकरण/सचिव/अध्यक्ष, एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भी किया है/मेरे द्वारा भेजे गए आवेदन/आवेदनों की विशिष्टियाँ इस प्रकार हैं :—

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन इस मामले के संबंध में न तो मेरे द्वारा और न ही मेरी ओर से ऐसा आवेदन फाइल किया गया था।

(4) उपर्युक्त प्रतिकर के संबंध में मैंने किसी न्यायालय अथवा अन्यथा किसी से भी कोई रकम प्राप्त नहीं की।

अथवा

प्रतिकर दावे में मे मैंने _____

रूपये की रकम प्राप्त की है, जिसकी विशिष्टियाँ इस प्रकार हैं :—

(5) मैं यह वचन देता हूँ कि उपर्युक्त प्रतिकर के संबंध में अगर किसी स्रोत से मैं कोई रकम प्राप्त करता हूँ तो उसके बारे में मैं एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अवश्य सूचित करूँगा।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से/भगवान के नाम पर शपथ लेते हुए यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि पैरा 1 से 5 में जो कुछ कथन किया गया है वह जानकारी के अनुसार सही है और मेरे द्वारा किसी तात्त्विक तथ्य को नहीं छुपाया गया है।

अभिसाक्षी

स्थान—_____

दिनांक—_____

टिप्पणी :

(1) शपथ पत्र किसी शपथ-प्रायुक्त, अथवा किसी सिविल न्यायाधीश अथवा किसी प्रथम श्रेणी उप-न्यायाधीश अथवा किसी मजिस्ट्रेट अथवा किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा और इसका न्यायिकेतर-कागज पर होना आवश्यक नहीं है।

(2) जो लागू न हो उसे काट दें।

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE
PRACTICES COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 1991

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by sections 18 and 66 of the Monopolies and Restrictive Trade Practice Act, 1969 (54 of 1969) and in supersession of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission hereby makes the following regulations, namely :

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title and commencement (1) These regulations may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations, 1991. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);

(b) "Any other person interested" referred to in Section 41 of the Act includes manufacturers, suppliers, wholesalers, retailers and the associations of the traders, consumers, employees of manufacturers and those engaged in the distributive trade.

(c) "Bench" means a Bench of the Commission formed under sub-section (2) of Section 16 ;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Commission appointed under Section 5.

(e) "Party" shall include complainant (whether individual consumer or registered consumer's or trade association, Director General, Central or State Government as the case may be, and shall include a respondent or respondents against whom any enquiry or the proceedings is instituted or relief is sought to be made but shall not include the informant under sub-clause (iv) of clause (a) of section 10 or clause (d) of section 36B:

Provided that for the purpose of this clause, in any enquiry or proceeding instituted or ordered by the Commission on its own knowledge or information, the Director General shall be deemed to be the only party for the conduct of such enquiry or proceedings against a respondent:

Provided further that when the complainant does not pursue or ceases to take interest in this complaint, the Director General shall, with the permission of the Commission, be entitled to take full charge of the proceedings ;

(f) "Party to an agreement" includes any persons deemed to be a party for the purpose of the Act ;

(g) reference to "Court", while applying provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall be understood to refer to the Commission and similarly, reference to "Plaintiff" or "defendant" shall be understood to refer to appropriate parties before the Commission;

(h) reference to "suits or petitions" while applying the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall be understood to refer to appropriate proceedings under the Act;

(i) "Secretary" means Secretary of the Commission and includes the Deputy Secretary, the Administrative Officer,

Joint Director (Legal) and Deputy Director (Legal) of the Commission;

(j) "Section" means section of the Act,

2. All words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Language of the Commission.—The proceedings of the Commission shall be conducted in English or Hindi.

4. Language of application and reference etc.—No application, reference, document or other papers contained in any language other than English or Hindi shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a translation thereof in English or Hindi.

5. Translation of documents.—The documents required to be translated into English or Hindi under regulation 4 shall be translated by a person appointed or approved by the Commission:

Provided that any translation, which is agreed to by the parties to the proceedings, may be accepted by the Commission in appropriate cases as a true translation.

6. Commission's Office.—The Central Office of the Commission shall open at such times as the Chairman may by general or special order, direct.

7. Adjournment of hearings.—The Commission may, if sufficient cause is shown at any stage of any proceedings, grant time to the parties or any of them and may from time to time adjourn hearing of the proceedings.

8. Ex-parte hearings.—Where on the day fixed for hearing or on any other day to which the hearing may be adjourned, if the parties to the proceeding do not appear, the proceedings, unless adjourned by the Commission, shall continue in the absence of such parties, not so appearing.

9. Pleadings before the Commission.—All applications, replies, rejoinders, supplemental pleadings or other documents which are required to be filed before the Commission, shall be typed on one side of the foolscap size paper in double space.

10. Inspection and certified copies of documents, papers etc. :—

(1) A party to any proceeding before the Commission may, subject to the provisions of sections 17, 18 and 60 on an application made by it in that behalf, addressed to the Secretary, be allowed to inspect or obtain copies of pleadings and other documents or records in the proceedings

on payment of fees and charges as may be specified.

(2) The Commission may, subject to the provisions of Sections 17, 18 and 60 on an application of a person, who is not a party to the proceedings, on sufficient cause shown, allow such person such inspection or to obtain such copies, as are mentioned in sub-regulation.

(1) on payment of such fee as may be prescribed.

(3) An inspection shall be allowed only in the presence of a Gazetted Officer of the Commission, and copies of documents of the proceedings shall not be allowed to be taken out only notes of the inspection may be made.

(4) Copies of the proceedings, required under sub-regulation (1) or (2), may be certified, as true copies, by the Secretary or such other officer, as may be authorised in that behalf by the Commission, on payment of such fee as may be prescribed.

(5) Every duly authorised officer, not below the rank of Under Secretary to the Central Government or State Government or the Director General of Investigation and Registration, shall at all reasonable times, be entitled free of charge inspection of the file of proceedings of the Commission and to take copies or extracts from any document therefrom. The Commission shall furnish such copies or extracts to the aforesaid officers as they may demand in writing.

11. Reports, Orders or Judgements of the Commission :—

(1) Every report, order, or judgment of the Commission shall be signed and dated by the Chairman and Members; Provided that the Chairman or a member who dissents with the final conclusion shall record his reasons, separately under his signature and date.

(2) If members of a Bench are equally divided in their opinions, they shall record their views, separately under their signatures and date, and then the Chairman, may, if he is not a Member of the Bench, give his opinion, or if he is a Member of the Bench or otherwise does not want to give opinion, may direct another Member to give his opinion, if deemed necessary, after hearing the parties and there after the case will be decided, in accordance with the views of the majority.

(3) Every report that may be required to be submitted to the Central Government under the

Act shall be sent to that Government under the signature of the Secretary.

12. Extension of time prescribed—Any time limit fixed in these regulations or in any order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged by an order of the Commission.

13. Effect of non-compliance and application of Code of Civil Procedure to matters not provided—

(1) Failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding, merely by reasons of such failure, unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

(2) Subject to the provision of sub-section (1) of section 12, where no specific provision has been made in these regulations, the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to the extent, as may be deemed expedient by the Commission, shall apply to the proceedings.

14. Service of notice or other documents—(1) Every notice or other document, required to be—

(a) served on or delivered to any person, may be sent by registered post, or by courier service, or by speed post addressed to the person or his agent, empowered to accept service, at the address furnished by him for service, or at the place where the person, or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain;

(b) delivered to or filed with the Secretary may be sent by registered post to the Secretary.

(2) An acknowledgement purporting to be signed by the addressee or his agent or an endorsement by a postal employee that the addressee or his agent refused to take delivery or certificate of the courier or speed post that the service has been effected, may be deemed to be a prima facie proof of service.

(3) Any notice or other document, required to be served on or delivered to a trade association, may, if the association is not a body corporate, be sent to the Secretary, Manager or other officer of the association.

(4) Every notice or other document, required to be served on the Central Government or the State Government as the case may be, shall be

addressed and sent to the Secretary of the appropriate Ministry or Department and shall be served in the manner specified in clause (b) of sub-regulation (1).

(5) The notice or document in respect of an enquiry may be served :—

- (a) where the enquiry is against a company or corporation on the Secretary, or on any director, or other principal officer of the company or corporation by leaving it or sending it by post addressed to the company or corporation at the registered office of such company or corporation or at the place where the company/corporation ordinarily carries on business;
- (b) where the enquiry is against a firm, the notice of enquiry may be served at the principal place at which the partnership business is carried on upon any person having, at the time of service, the Control or management of the partnership business or upon any one or more of the partners of the firm;
- (c) on the proprietor in case of a sole-trading firm.

15. Costs (1) The Commission in its discretion may, subject to such conditions as may be specified in its order, determine costs of proceedings.

(2) The costs shall be paid within thirty days from the date of the order or within such time, as the Commission may, by order, direct.

(3) The order of the Commission, awarding costs, shall be executed in the same manner as the order of a Civil Court and the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall apply to the execution of such order.

16. Enforcement of orders passed by the Commission—(1) The Secretary shall ensure enforcement and compliance of the orders passed by the Commission, by the persons concerned, and, if necessary, seek the order of the Commission for such investigation, as may be required, to be carried on by the Director General or any other officer, not below the rank of Assistant Director of the Commission.

(2) The Director General, in appropriate cases, shall bring to the notice of the Commission non-

compliance of the orders of the Commission and may seek directions for investigation into such non-compliance.

CHAPTER II

PRELIMINARY INVESTIGATION

17. Order of investigation and its effect—(1) The Commission may, on receipt of a complaint, reference, application or information, or as the case may be, on its own knowledge in the matter of restrictive or unfair trade practice under clause (a) of sections 10 or section 36B order a preliminary investigation by the Director General or by an officer not below the rank of Assistant Director.

Explanation—Whenever the Commission directs a preliminary investigation into any complaint under sub-clause (1) of clause (a) of section 10 or a preliminary investigation is compulsorily required under section 36C in respect of a complaint by any Association, such investigation shall be made by the Director General.

(2) Order of investigation by the Commission under sub-regulation (1) shall be deemed to be the commencement of enquiry under the act.

18. Submission of Preliminary Investigation Report—The Commission shall direct, by order, the Director General or any officer of the Commission, as the case may be, to complete the preliminary investigation and submit a report (5 copies besides such additional copies as is the number of respondents) within such time as it may fix in the order;

Provided that the Commission may, on a request made by the Director General or by the officer of the Commission conducting investigation, extend the time for submission of report.

19. Action on Preliminary Investigation Report—(1) The Commission in its discretion and subject to the provisions of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, may at any stage of the inquiry, bring on record, the report of the Director General or any officer of the Commission, or as the case may be, any information or other material, collected by the Director General or any officer of the Commission.

Provided that the Commission shall not bring on record such part or parts of the report, information or material, the disclosure of which, in the opinion of the Commission, is not relevant or is not in public interest.

(2) The Director General shall be entitled to reply where the report brought on record is sought to be rebutted by any party.

20. Further investigation by the Director General etc.—(1) Where the Commission, on the perusal of a report of the Director General or any officer of the Commission submitted under regulation 18, is of the view that a further investigation is necessary, it may by order direct the Director General or such officer of the Commission to make such further investigation, as the Commission may think necessary, and submit a further report.

(2) Where on the perusal of a report under regulation 18 or sub-regulation (1) of this regulation, or both as the case may be, the Commission is of the opinion that no prima-facie case is made out for the issuance of notice enquiry in respect of all or any of the allegations, it may drop the proceedings in respect of all or, as the case may be, any of the allegations;

Provided that where investigation has been made on the basis of a complaint, reference or application under sections 10 or 36B or 31, the Commission shall give the complainant, the concerned Government or, as the case may be, the Director General, but not the informant under sub-clause (iv) of clause (a) of section 10 or clause (d) of section 36B, an opportunity of being heard before passing order to drop the proceedings in respect of all or any of the allegations;

Provided further that subject to the provisions of section 60, the registered consumer association or trade association or a consumer, who has filed the complaint, on the basis of which an investigation has been made, may be supplied with a copy of the preliminary investigation report for the purpose of enquiry under the Act.

21. Enquiry on the basis of preliminary investigation report :—Where the Commission after considering the report under regulation 18 or sub-regulation (1) of regulation 20, or both as the case may be, is of the opinion that an enquiry must be held into a restrictive trade practice or an unfair trade practice, it shall so order and such enquiry shall be held in accordance with the procedure laid down in Chapters IX and X of these regulations.

22. Enquiry into monopolistic trade practice on the basis of preliminary investigation report—Where the Commission after considering the report under regulation 18, or sub-regulation (1) of regulation 20, or both, as the case may be, is prima-facie of the view that an enquiry shall be held into a monopolistic trade practice under clause (b) of section 10, the procedure, as laid down for restrictive trade practice in Chapter IX, shall, mutatis mutandis, be followed. After enquiry, the Commission shall proceed as provided in section 31 of the Act.

CHAPTER III

DUTIES AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR GENERAL

23. To represent the Commission before Supreme Court or High Court—In the event of an appeal under section 55, or application for grant of Special Leave to Appeal under article 136 of the Constitution, or a writ petition under article 226 or 32 of the Constitution, the Director General shall represent the Commission before the Supreme Court or the High Court, as the case may be, except in those cases, where the Director General has himself filed an appeal or special leave to appeal against an order of the Commission.

24. Filing of application before the Director General—The applications filed before the Director General under sub-section (3) of section 36 shall be accompanied by five additional copies thereof, besides as many additional copies, as is the number of respondents.

25. Filing of application by Director General for seeking directions of Commission—Where the Director General files an application for seeking any directions of the Commission for disposing of any application under sub-section (e) of section 36, he shall make an application alongwith four extra copies thereof to that effect and such an application shall contain information and be accompanied by the following documents.

- (a) a copy of the application of the party concerned;
- (b) a copy of agreement in (quadruplicate) and
- (c) comments of the Director General on the application.

26. Disposal of the Director General's application by the Commission—On the receipt of application under regulation 25, the Commission may, if it considers necessary, give the applicant an opportunity of being heard. The Director General shall also be heard in such proceedings and for this purpose intimation about the date of hearing shall be sent to him.

CHAPTER IV

ENQUIRIES AND INVESTIGATIONS BY OFFICERS OF THE COMMISSION

27. Mode of Investigations.—(1) Without prejudice to the provisions of regulations 17, 18, 19 and 20 the Commission may, at any time, direct the Director General or any one or more of its officers, not below the rank of Assistant Director, to (a) study, (b) investigate and report; or furnish any information in respect of any trade practices, which constitute or contribute to monopolistic, restrictive or unfair trade practices in any trade or are alleged to have been practised by any producer, distributor, dealer, agriculturist, processor, miner or investor in respect of any application or reference under section 61 or Chapters III, IV, V and VI of the Act, and for this purpose, the Commission may give to the Director General or such officer or officers of the Commission any direction, as it may deem fit and may fix time, within which the report is to be submitted or information furnished. If any such report or information appears to the Commission to be insufficient, the Commission may give directions for a further or supplementary report or information thereon.

(2) The provisions of regulations 19 and 20 shall, mutatis mutandis, apply to the report furnished or as the case may be, the information, material and evidence if any, collected under sub-regulation (1) for the purpose of any action, proposed to be taken thereon.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR REFERENCE UNDER CHAPTERS III AND IIIA OF THE ACT BY THE GOVERNMENT

28. References received under sections 21, 22, 23, 27 and 27A of the Act—(1) Where a reference is received by the Commission from the Central

Government, under sections 21, 22, 23, 27 and 27A, the Commission may publish short particulars concerning the reference by way of a notice in such daily newspapers for inviting comments regarding the proposal within such time as may be mentioned in the notice. The comments shall be sent to the Commission in quadruplicate and the person sending the comments shall state whether he would like to participate in the public hearing before the Commission.

(2) In case of references under section 27 or 27A, the Commission shall, after such investigation as it deems fit, formulate its tentative opinion. It shall, thereafter, furnish to the owner of the undertaking concerned, a copy of the reference and its tentative opinion. The owner of the undertaking(s), concerned, may, within such time as the Commission may fix in each case, file a statement of its objections and/or suggestions to or in respect of the tentative opinion.

(3) The Commission may address letters to the applicant, concerned Government Department and such other persons, calling for such particulars, and information, as in the opinion of the Commission may be relevant to the reference received by the Commission. The replies to such letters to the Commission shall be furnished in quadruplicate.

(4) The Commission may call the applicant concerned, owner of the undertaking(s), any government official and any other person, for such discussion, as it may consider necessary for the enquiry.

(5) The Commission may visit such establishment, including that of the applicant, or concerned owner of the undertaking(s) and hold discussions with their representatives, if in the opinion of the Commission such visits and discussions may be useful for the enquiry.

(6) The Commission may depute such of its officers and staff to such places and to meet such persons, as it may deem appropriate, for enquiries and discussions, relevant to the reference and take into consideration the reports of such officers.

(7) The applicant, the concerned owner of the undertakings, the persons, who have sent their comments and expressed their desire to participate in the public hearing and such other persons as the Commission may determine, shall be intimated about the date of public hearing not less than 21

days before the date fixed for hearing. The persons, who have sent their comments and an intimation that they would like to participate in the public hearing, shall file with the Commission, not less than 10 days before the date of public hearing, a statement containing the submissions that they wish to make at the public hearing.

(8) Subject to the provisions of sections 17 and 18 the Commission shall hear the persons, to whom an intimation of the public hearing is sent under sub-regulation (7). The Commission may, if it considers necessary, examine witnesses, including experts in any field. The persons so examined may, at the discretion of the Commission, be cross-examined by any of the parties, to whom an intimation of public hearing is sent.

(9) In an enquiry to be made by the Commission under this regulation, the Central Government shall be entitled to be represented by such officer as it may depute. The persons concerned, appearing in person or represented by a counsel specifically authorised by them to act on their behalf, may be heard.

CHAPTER VI

ENQUIRIES UNDER CLAUSE (b) OF SECTION 10 AND SUB-SECTION (4) OF SECTION 37

29. In the case of a reference under section 31 of the Act or upon its own knowledge and information under clause (b) of section 10 in respect of monopolistic trade practice, the Commission shall direct investigation to be carried out by the Director (Investigation and Enforcement) of the Commission and on receipt of preliminary investigation report it may proceed with the enquiry and for that purpose such procedure be followed *mutatis mutandis* as is laid down under chapter IX of these regulations. After such enquiry the Commission shall proceed in accordance with the provisions of section 31.

CHAPTER VII

CONSULTATIONS UNDER SECTIONS 24, 27, AND 27A AND REFERENCES UNDER SECTION 61

30. Where the Central Government required the Commission to make a report under section 61 or where the Central Government consults

it under sections 24, 27 or 27A the Commission may decide the procedure to be followed, in accordance with the circumstances of each case. For the purpose of making a report in such cases, the Commission may employ such experts as it may consider necessary.

CHAPTER VIII

MINIMUM RESALE PRICE MAINTENANCE (EXEMPTION) APPLICATIONS

31. Exemption from Sections 39 to 40—The Director General or any other person interested, who wishes to make a reference to the Commission under section 41 for exemption from the operation of sections 39 and 40, shall make an application in writing, clearly stating :—

- (a) the nature of interest claimed by the applicant that entitles him to make the reference;
- (b) the class of goods to which it relates and the sub-classes thereof, if any;
- (c) the trade name or names, or trademark or marks, by which name or mark the goods are identified in the market;
- (d) the names and addresses of other persons, dealing in the class of goods for which application is being made before the Commission, as far as the applicant can furnish such information; and
- (e) the clause or clauses of sub-section (1) of section 41 on which reliance is placed for making application and the reasons in support of the same.

32. Application to contain necessary evidence—The application referred to in regulation 31 shall be supported by evidence regarding facts mentioned therein and be verified.

33. Application by more than one person—Where more than one person deals with similar class of goods for which exemption under section 41 is sought, the application may be made jointly by such persons.

34. Common application—A common application may be made for a number of classes of goods appearing to be closely related. However the Commission may ask the applicants to make separate applications, if the Commission during the course of considering such application, comes to the conclusion that separate applications are necessary or desirable.

35. Separate application for each class of goods—Where an exemption is sought in respect of more than one class of goods that are not closely related, a separate application shall be made in respect of each class of such goods.

36. Issue of notice, etc.—

(1) On receipt of an application under regulation 31 if the Secretary is of the opinion that there is no *prima facie* substance in the application, he may place the same before the Commission for preliminary hearing and inform the applicants and the Director General of the date of such hearing. The Commission may, after hearing the applicants, and the Director General, reject the application.

(2) The Secretary shall, in respect of applications, which are not rejected in limine, give notice to the concerned parties and shall also give public notice by advertisement in such daily newspaper or newspapers as may be decided by the Commission by a general or special order. The notice shall briefly state the relevant details including the class or classes of goods in respect of which the application is made and the names and complete addresses of the parties making the application.

(3) The Secretary shall send a copy of the notice to the Secretary of the Ministry or Department, dealing with the subject matter, of application, informing him that the Ministry or Department may, if it so desires, send its comments to the Commission, regarding the subject matter of the application.

37. Representations—Representations, opposing or supporting the reference, shall be filed before the Commission within 30 days of the publication of the public notice in the daily newspapers and shall state the nature of the interest of the party making representation and whether he supports or opposes the maintenance of minimum re-sale price in respect of all or any of the goods to which the notice relates. Such representations shall comply with the other requirements of regulation 58 and shall be verified in the manner laid down in regulation 49.

38. Preliminary hearing—(1) After the expiry of the time limit for filing the representations under regulation 37 the Commission shall fix a date for the preliminary hearing. The applicant, who had filed the reference before the Commi-

ssion shall state his case indicating broadly as to what would be his submissions before the Commission. During the course of hearing, the applicant shall be served with the copies of the representations received in response to the public notice, and he shall file his reply within 14 days of the service of such notice on him.

(2) If, during the course of the preliminary hearing, it appears to the Commission that the prayer made in the reference and the circumstances of the case are substantially similar to those considered in some earlier proceedings disposed of by it, it may direct that the reference be disposed of summarily.

(3) Where the applicant or any respondent applies to the Commission for an order that any proceedings pending before the Commission be consolidated and heard together, the two proceedings may, if the Commission so directs, be consolidated and heard together.

39. Investigation by Director General etc., regarding applications filed by any other person interested—

(1) After the hearing under regulation 38 and after taking into account the representations received, the Commission may, if it thinks necessary refer the matter to the Director General or any other officer of the Commission for investigation in such manner as it may, by order, direct.

(2) The Director General or any other officer of the Commission not below the rank of Assistant Director shall make a report containing the findings of his investigation to the Commission within 90 days from the date of direction for investigation or within the period as the Commission may extend.

40. Directions—After receipt of the report of the Director General or any other officer of the Commission and after taking into account the submissions made by the parties to the proceedings, during the course of the preliminary hearing and those contained in the representations received and the replies filed by the applicant, under regulation 37, the Commission—

(a) shall determine which of the persons, who have filed representations before the Commission, in response to the public notice, may be permitted to take part or represented in the proceedings before it.

(b) may, by order, direct that some or all of the persons who have filed representations before it shall be represented by such common representative, as it may deem fit;

(c) may, by order, direct that the reference may be so amended to include therein or to exclude therefrom any goods or in any other manner as it may deem fit;

(d) may give such other directions, as it may think fit including:—

- (i) the amendment of the notice of hearing or any representation, answer or reply;
- (ii) the supply of further and better particulars;
- (iii) the delivery of interrogatories;
- (iv) the admission of any facts or documents;
- (v) the discovery or further discovery of any documents and inspection thereof;
- (vi) the admission of any document in evidence;
- (vii) the mode in which evidence is to be given;
- (viii) the taking and recording of any evidence including the appointment of a Commissioner for the purpose; and
- (ix) an investigation of the cost in respect of any class of goods, in producing or supplying any goods or in applying any process of manufacture to goods and the manner in which the result of such investigation is to be brought before the Commission at the final hearing.

41. Service of notice of hearing—The Secretary shall serve a copy of the hearing notice, not less than 21 days a notice in writing to the applicants and the persons entitled to take part in the proceedings by virtue of directions given under items (a) and (b) of Regulation 40 and such a notice shall, in the case of persons entitled to take part in the proceedings under such direction be accompanied by a copy or copies of the reference.

42. Final hearing—The hearing, regarding these references, shall be held in accordance with regulation 70.

43. Interlocutory order—Where a direction has been given under regulation 38 for the determination of the reference in a summary way or for consolidation the Commission may, at the hearing, unless it is satisfied that the relevant facts and circumstances of the reference differ in some material respect from the facts and circumstances considered in the reference,

- (a) make an order on the application in a summary way without hearing evidence, or on such evidence whether oral or documentary, as it may think fit; and
- (b) by order give any directions, which the Commission should have given under section 41, if the issue had been determined after a final hearing, or defer the making of any such order giving any direction until all other issues in the proceedings have been disposed of.

44. Final order—After hearing the applicants and the persons who have filed representations before the Commission and have been permitted to take part in the proceedings, and after examination of such witnesses, as may be called upon by the Commission, it shall pass final orders on the application/applications. A copy of such order duly authenticated by the Secretary and bearing the seal of the Commission shall be served on the applicant and other persons, permitted to take part in the proceedings.

CHAPTER IX

PROCEEDINGS UNDER SECTION 37 OF THE ACT

45. Complaint under section 10(a)(i)—(1) A complaint under sub-clause (i) of clause (a) of section 10 of the Act shall contain the facts complained of, which constitute restrictive trade practice.

(2) A complaint by any trade association or any registered consumers, association shall be signed and verified by any office bearer of the association, who is authorised in writing by the President of that association and a complaint by an individual consumer shall be signed and verified by such consumer in the manner prescribed in regulation 49.

46. Reference by Government—A reference made by the Central Government or a State Government under sub-clause (ii) of clause (a) of section 10 shall, similarly, contain the facts which constitute a restrictive trade practice, and be signed and verified in the manner prescribed in regulation 49.

47. Application by Director General—An application under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 by the Director General shall contain the facts, which constitute a restrictive trade practice and if it is in relation to any agreement registrable under section 33 of the Act, shall set-out such portions of the agreement as may be necessary to bring out the facts complained of and be signed and verified by the Director General in the manner prescribed in regulation 49.

48. Copies of complaint, reference etc.—The original complaint, reference or the application, as the case may be, referred to in regulations 45 to 47, shall be accompanied by four copies thereof for the Commission's record and such additional number of copies thereof, as may be necessary, for being served on respondents or other interested parties, referred to in the respective complaint, reference or application.

49. Signing of the pleading etc. to be filed before the Commission—All complaints, references, applications, statements of the case and other pleadings, to be filed before the Commission, shall be signed by the parties or their duly authorised representatives and verified. The person verifying shall specify, by reference to the numbered paragraphs, what he verifies on his own knowledge and what he verifies on information, received and believed to be true. The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed.

50. Proceedings before the Commission—It on receipt of a complaint, reference or application or information under clause (a) of section 10 of the Act, and on consideration of any evidence on record or preliminary investigation report, if any, the Commission, is of the opinion that there are sufficient grounds to issue a process, requiring the attendance of the person or persons complained against, such a process shall be issued and it will be called NOTICE OF ENQUIRY.

51. NOTICE OF ENQUIRY—(1) The notice of enquiry, referred to in regulation 50, shall be accompanied by :—

- (i) in the case of complaint under sub-clause (i) of clause (a) of section 10 of the Act, a copy of such complaint;
- (ii) in the case of reference under sub-clause (ii) of clause (a) of section 10 of the Act, a copy of such reference;
- (iii) in the case of an application under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 of the Act, a copy of such application; and
- (iv) in case of an enquiry under sub-clause (iv) of clause (a) of section 10 of the Act, a concise statement of material facts on which the notice is based, or a copy of the preliminary investigation report or relevant extract thereof.

(2) A combined notice under two or more sub-clauses of clause (a) of section 10 of the Act, may be directed to be issued, together, by the Commission.

(3) Every such notice shall specify the date and place of hearing before the Commission

52. Notice may relate to a number of agreements or trade practices—A notice may relate to one agreement or to a number of agreements or one trade practice or to a number of trade practices appearing to the Commission to be related in such a way as to make it desirable that they should be considered in the same proceedings,

53. Notice to bear the Commission's seal—A notice shall bear the Commission's seal and be signed by the Secretary and when returned after service shall be filed by the Secretary.

54. Service of Notice—Subject to regulation 57, the Commission shall cause a copy of the notice to be served on such parties, as the Commission may decide and such of those parties, as the Commission may direct, shall be respondents to the proceedings.

55. Service of notice on a trade association—The Commission may, if it thinks fit, serve a copy of notice on any trade association, whose members or any of whose members are parties to any agreement or are alleged to be guilty of a trade practice to which the notice relates, and trade association may, if the Commission so directs, be made respondent to the proceedings, without

prejudice to any application under regulation 57 for the representation of members of the association by the association.

56. Publication of notice of enquiry and orders passed by the Commission—(1) Short particulars regarding enquiry by the Commission and orders passed by the Commission may be published at such time and in such manner and in such daily newspapers, by the secretary as the Commission may be any general or special order, direct.

(2) The Secretary may also issue press release in such a manner as he may deem fit, or as directed by the Commission.

57. Persons having common interest—(1) Where there are a number of persons having common interest, whether as complainants, respondents or as parties who are served with notice under regulations 50, 53, 54 or 55, the Commission may, by order, direct that any particular complaint, respondent or party shall appear in the proceedings on behalf of or for the benefit of all persons, having common interest and the Commission shall, in such a case, give notice of proceedings to all such persons having common interest either by personal service, or, where the persons to be served are in large numbers, or for any other cause such personal service is not reasonably practicable, by public advertisement, as the Commission may in each case direct.

(2) Any person, on whose behalf or for whose benefit any party appears in the proceedings, may apply to the Commission to be made a party to the proceedings.

(3) The Commission shall in such cases determine as to who shall bear the costs of any of the public advertisements or personal service.

58 Appearance of the parties—(1) A respondent on whom a notice has been served and who wishes to be heard in the proceedings shall, not less than 10 days before the date of hearing, specified in the notice, enter appearance in the office of the Commission by delivering to the Secretary with a copy to Director General, a memorandum with five additional copies, indicating that he wants to be heard in the proceedings and containing the name of his advocate or the name and full official and residential address of his authorised representative and duly authorised to accept service of process.

(2) The advocate or authorised representative, named by the respondent, shall file vakalatnama/ power of attorney at the time of appearance.

Explanation—An authorised representative shall either be a member of the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Costs and Works Accountants of India, or the Institute of Company Secretaries of India or a person holding qualification of post-graduate or higher in Commerce, or Economics or Management and furnish his full official and residential addresses; PROVIDED that in the even of misconduct, the Commission may disallow, any of the aforesaid authorised representatives to appear before the Commission.

59. Reply to the notice:—(1) Every respondent who has entered appearance shall while entering appearance deliver to the Secretary a reply to the notice (five copies besides as many copies as in the number of respondents) which shall include—

- (a) particulars of each of the circumstances contained in section 38 of the Act, on which he intends to rely; and
- (b) particulars of the facts and matters, alleged by him to entitle him to reply on section 38.

(2) Where the respondent relies on any document (whether in his possession or power or not) as evidence in support of his reply he shall enter such document in a list to be added or annexed to the reply. Where any such document is not in the possession or power of the respondent he shall, if possible, state in whose possession or power it is. The respondent shall, also send or supply copy of reply to the notice of enquiry to the complainant (whether individual or registered consumer association or trade association) alongwith a copy of list of documents relied upon.

(3) The document which ought to be entered in the list referred to in sub-regulation (2) and is not so entered, shall not without the leave of the Commission, be received in evidence on behalf of the respondent.

(4) The Secretary shall, as soon as may be furnished copy or copies to the Director General or other parties concerned, including the complainant, in case copies have not been supplied to any one of them by the respondent.

60. Notice for inspection of documents by Director General—Every respondent shall, within seven days after receiving notice in that behalf from the Director General, produce for his inspection the documents, or such of them, as may be specified, in the notice and shall permit him to make copies thereof;

Provided that nothing herein contained shall effect the right of the respondent to claim, for reasons to be stated, privilege for any of the said documents.

61. Filing of pleadings—No pleading, subsequent to the reply, shall be presented except by the leave of the Commission upon such terms as the Commission may think fit; but the Commission may at any time require a pleading or rejoinder or a supplemental pleading from any of the parties and fix a time for presenting the same.

62. The Commission may strike out the whole or part of the pleadings—The Commission may, on the application of the party, strike out the whole or any part of the reply, rejoinder, pleading or supplemental pleading, which appears to the Commission liable to be struck out in accordance with the provisions of rule 16 of order VI of the Code of Civil Procedure, 1908, and in that event, allow further time for the delivery of the reply, rejoinder, pleading or supplemental pleading.

63. Amendments in proceedings—(1) The Commission may, at any time, amend any defect or error in any proceeding including notice of enquiry and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or dependent on, such proceedings.

(2) The Commission may at any time or stage of the proceedings allow any party to alter or amend his reply to the notice of enquiry, rejoinder, pleading or supplemental pleading in such manner and on such terms, as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy.

64. Joinder of the parties—(1) Any party to the proceedings may, at any time, apply to the Commission (with four additional copies of the application) for an order that any person, not already a party, be added as a party to the pro-

ceedings and shall give notice of application to all other parties and to the persons sought to be added.

(2) The Commission may, at any stage of the proceedings either of its own motion or on the application of any parties to the proceedings on such terms as may appear to the Commission just and equitable, order that the name of any parties improperly jointed be struck out, and the name of any person, who sought to have been joined or whose presence before the commission may be necessary in order to enable the Commission, effectively and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the proceedings be added.

(3) Where any party is added or name of the parties is struck out, the pleadings, unless the Commission otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary.

(4) The provisions of order I of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply *mutatis mutandis* to these proceedings.

(5) Any complainant, applicant or Government authority who makes complaint, application or reference under sub-clauses (i) to (iii) of clause (a) of section 10 of the Act, as the case may be, shall be a party and shall be entitled to participate, file pleadings and be heard. He shall also be entitled to copies of application, if any, pleadings, filed by the Director General or any other person, during the proceedings of the enquiry. An informant may, at the discretion of the Commission, be heard in the proceedings, if he makes a request in that behalf and the Secretary may, and if so directed by the Commission shall, furnish to him or in a copy of the documents filed with him under regulations 45, 46, 47, 58, 59 and 63.

65. Application for directions—(1) On the date of hearing, the Commission may, either sub-moto or on an application by any party, give such directions, as it may think fit, with regard to the following matters:—

- (a) the amendment of the notice of enquiry or any representation, answer or reply;
- (b) the delivery of further and better particulars;
- (c) the delivery of interrogatories;
- (d) the admission of any facts or documents

- (c) the discovery or further discovery of any documents and inspection thereof;
- (f) the admission, in evidence of any document;
- (g) the mode in which evidence is to be given;
- (h) the taking and recording of any event including the appointment of a Commissioner for that purposes;
- (i) the investigating of the cause in respect of any class of goods in producing or supplying any goods or in applying any process of manufacture to goods and the manner in which the result of such investigation is to be brought before the Commission at the final hearing; and
- (j) any other matter, as may be considered necessary or proper for the purpose of enquiry.

(2) In any enquiry, where issues have been framed on any question of law or fact and the Director General, the complainant or the person making the reference, as the case may be has not filed the list of documents on which he relies, he shall file the list on the date, when the issues are framed or within such time as the Commission may direct.

66. Admission of documents by a party in enquiry proceedings—(1) Any party to the enquiry may call upon any other party to the enquiry to admit within fifteen days from the date of the service of notice of enquiry any documents relevant to the enquiry.

(2) Where a party unreasonably neglects or refuses to admit documents after the service on him of the notice to admit documents, the Commission may direct him to pay costs to the other party by way of compensation.

67. Interlocutory applications—Except where these regulations otherwise provide or the Commission otherwise directs, every interlocutory application shall be made on not less than seven days notice to every other party concerned in the subject matter of the application and the notice shall include particulars of the directions or orders to be sought.

68. Proving of facts—All facts required to be proved at the hearing shall, unless they are admitted, be proved as under:—

(1) by oral examination, cross examination and examination of witnesses or by affidavits in accordance with order 19 of the Code of Civil Procedure, 1908 read with section 12(1)(c) of the act; and

(2) by documentary evidence consisting of original or authenticated copies of documents, entries in the books or authenticated copies thereof or film audio or video tapes.

69. Scientific, technical and statistical information—In case of scientific, technical or statistical information relevant to the proceeding, the same may, by the permission of the Commission, be proved by production of specified scientific technical economic or trade publication or work of reference, containing such information.

70. Final hearing—The final hearing shall take place in the open court.

Provided that if the Commission is satisfied that it is in the public interest that the hearing or part thereof should not take place in open court or that evidence may be given as to a secret process of manufacture or as to the presence, or absence, or situation of any mineral or other deposits or as to any similar matter the publication of which is likely to damage substantially the legitimate business interest of any person, it shall and may in other case in which it appears proper to the Commission to do so, order that the hearing or such part thereof as the Commission may direct, shall take place in camera.

71. Determination of issue in a summary way—If on the hearing of an application it appears to the Commission that the relevant provisions of the agreement or any other facts or circumstances relating to the agreement or to a trade practice, or practices, are substantially similar to those considered in previous proceedings before the Commission; it may direct that the issue be referred for determination in a summary way.

72. Directions in case of determination of issues in a summary way—Where a direction has been given under regulation 71, the Commission may at the hearing, unless it is satisfied that the relevant provisions of the agreement or trade practice or practices or the circumstances of the case differ in some material respects from the

revisions or trade practice or practices, and circumstances considered in the previous proceedings :—

- (a) determine the issue in a summary way without hearing the evidence or on such evidence whether oral or documentary as it may think fit; and
- (b) by order give any direction, which the Commission could have given under section 37 of the Act if the issue had been determined after final hearing in the ordinary way or defer making of any such order giving any direction until all other issues in the proceedings have been disposed of.

73. Calling of comments on complaints—The Commission may, in its discretion, instead of directing investigation or instituting enquiry straightway, on a complaint under section 10(1) (i) or 36B (a) or information under section 10(a) (iv) or 36B(d) of the Act, sent a copy of the complaint or information to the person against from whom the same is made calling for comments for enabling it to either do the needful as desired by the complainant or informant or send his own version. The Commission may, thereafter on receipt of the reply or after expiry of the time fixed for sending the comments, proceed with the complaint or information in accordance with the provisions of the Act and the regulations.

74. Final Orders—After hearing the complainant or the applicant or any Government authorities making a reference, or the Director General, as the case may be, and the respondents and other persons who have filed representations before the Commission and who have been permitted to take part in the proceedings and after examination of such witnesses as called upon by the Commission, it shall pass final orders on the complaint, application, reference, etc. A Copy of such order duly authenticated the Secretary and bearing the seal of the Commission shall be served on the complainant, applicant, Government authorities making the reference, the respondent, as also on such other Government authorities and other persons permitted to take part in the proceedings.

CHAPTER X

PROCEEDINGS UNDER SECTION 36D OF THE ACT

75. Inquiries into unfair trade practices—The procedure laid down in Chapter IX of these regulations for inquiries into restrictive trade practices shall mutatis mutandis, apply to the inquiries into unfair trade practices under section 36D of the Act, subject to the modification that :

- (i) reference to sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) of section 10 of the Act shall be construed as a reference to the corresponding clauses (a) to (d) of section 36B, and
- (ii) reference to section 37 of the Act shall be construed as a reference to section 36D of the Act.

CHAPTER XI

APPLICATIONS UNDER SECTIONS 12A AND 12B

76. Temporary Injunction—Every application under section 12A of the Act for issuance of a temporary injunction shall be supported by an affidavit of the person making the application stating the facts which constitute monopolistic, restrictive or unfair trade practice and the circumstance whereby it is intended to be proved that the said trade practice is likely to affect the public interest or the interest of any trader or traders generally, or any consumer or consumers generally. The application shall be accompanied by five extra copies and one additional copy for each respondent. The application shall be filed with the Secretary, who shall forthwith place the application before the Commission for disposal.

77. Application for compensation—(1) Every application made under section 12B of the Act for compensation shall be supported by an affidavit of the person making the application in the form appended to these regulations stating the particulars and the extent of the loss or damage caused as a result of the alleged monopolistic, restrictive or unfair trade practice and also stating that he has not filed any application either before the Commission or before any authority under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) and be filed with the Secretary with five extra copies and one additional copy for each respondent.

(2) The Commission may, before making any order under section 12A or section 12B of the Act, direct the Director General to make such investigation as may be deemed necessary into the allegations and submit a report thereon.

CHAPTER XII AMENDMENT OF REVOCATION OF ORDER

78. Review application—An application under sub-section (2) of section 13 of the Act shall contain facts or the reasons as to why the order sought to be reviewed is liable to be altered, modified or set aside. It shall be supported by an affidavit. No order shall be changed, altered, modified or set aside without an opportunity of being heard, having been given to the person in whose favour the order is and the Director General.

79. Rectification of errors—Any clerical or arithmetical mistakes in any proceedings, amendment of proceedings, declaration or order of the Commission or error therein arising from any accidental slip or omission may, at any time, be corrected by the Commission either on its own motion or on the application of any party and the provisions of sections 152 and 153 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall be applicable in this respect.

[F. No. 8(41)/MRTPC/87]

H. K. Malik, Jt. Director.

FORM

BEFORE THE MONOPOLIES AND RES-
TRICTIVE TRADE PRACTICES
COMMISSION, NEW DELHI

COMPENSATION APPLICATION NO.
OF 19

(-----)
(Name and addresses of the applicant)

Applicant

Versus

(Name and address of the respondent)

Respondent

COMPENSATION APPLICATION UNDER SECTION 12B OF MONOPOLIES AND RE- STRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Sir,

The applicant begs to submit as under :—

1. Brief facts of the claims.
2. Brief narration of monopolistic, restrictive or unfair trade practice.
3. Particulars of loss, damage or injury and the amount payable.
4. Particulars of proceedings, if any, under the Consumer Protection Act or any other Law in respect of the same matter.

PRAYER

(State exact amount, rate of interest or any amount on any other account)

Signature of the applicant

VERIFICATION

Verified at ----- on the ----- day
of ----- 19. The contents of above paras are
true to the best of my knowledge and nothing has
been canceled therefrom.

Signature of applicant.

Encls : 1. Attested Affidavit.

2. Attested photocopy of deposit receipt
(if applicable.)

AFFIDAVIT

I ----- s/o -----
aged ----- years, resident of -----
swear in the name of God/Solemnly affirm and
state as under :

(1) I have gone through my application for grant of compensation under Section 12B of the MRTP Act, 1969. The same is correct. The annexures are copies true to their originals and true translation of the originals.

(2) The aforesaid is the only application/I made such an application to the Director General of Investigation and Registration/Secretary/Chairman, M.R.T.P. Commission in addition to the aforesaid application. The particulars of the application/applications sent by me are as under:

(3) No such application was filed either by me or on my behalf under the consumer Protection Act, 1986 in respect of the same matter.

(4) I did not receive any amount in respect of the aforesaid compensation from any one whether through any Court or otherwise.

OR

I received a sum of Rs. out of the compensation claim particulars of which are as under:—

(5) I undertake that if I receive any amount from any source in connection with or relating

to the aforesaid compensation, I will intimate the same to the [M.R.T.P. Commission.

DEPONENT

VERIFICATION

I solemnly affirm/swear in the name of God that whatever is stated in paras 1 to 5 above is true to my knowledge and no material fact is cancelled by me.

Place :

Date :

DEPONENT

Note:

(1) The affidavit shall be attested by an Oath Commissioner or a Civil Judge or a Sub-Judge 1st Class or a Magistrate or a Notary Public and need not be on a Non-Judicial paper.

(2) Strike out whichever is not applicable.